happy when one day you become a very senior Member of this House and occupy the front bench as the leader. But now please go back to your seat. Do not drag me into a situation where Mr. Kulkarni will cast aspersions on me... (*interruptions*)...

Re. TRANSPORTATION OF GOODS BY FOREIGN SHIPPING LINES

SHRI JAGESH DESAI (Maharasthra) : Madam, the Surface Transport Minister, while answering a question, had stated that he wanted to have a strong shipping industry. But now it has been reported in some of the newspapers that MMTC and STC can transport their goods by any shipline, it may not be an Indian shipline alone They could transport it by foreign shiplines too. Madam, if this is done, then I am afraid, our shipping industry will go to dogs. Up till now, an option was given and the goods used to be usually transported by the Indian shiplines. But now since the Government has decide that any shipline could be used, our shipping industry will be badly affected I would like the Minister to say something on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the calling attention.. (*Interruptions*)...

SHRI N. E. BALARAM (Kerela) : Madam, Mr. Desaid has raised a very serious issue...(*interruptions*)..

SHRI JOHN F. ERNANDES (Goa): Madam, the Prime Minister has returned from Carcacas. There should be a statement....(*Interruptions*)..

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Madam, the issue that Mr. Desai has raised pertains to the very survival of the Indian shipping industry. It is a very important issue... (*Interruptions*)....

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

THE PLIGHT OF HANDLOOM WEAVERS IN ANDHRA PRADESH RESULTING IN STARVATION DEATHS OF MANY OF THEM AND THE ACTION TAKEN BY GOVERNMENT IN REGARD THERETO

[The Vice-Chairman (Shrimati Jayanthi Natarajan) in the Chair

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Madam, I beg to call the att attention of the Minister of of Textiles to the plight of handloom weavers in the State of Andhra Pradesh resulting in starvation deaths of many of them and the action taken by Govern- Government in regard thereto.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गेलोत) : महोदया, आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की मृत्यू पर माननीय सदस्यों की चिंता से मैं पूर्णत: सहमत हूं। यह अवसर इस बात का नहीं है कि यह देखा जाए कि यह मृत्यू भूखमरी कारण हुई या किसी और कारण से। हम रे लिए तो यही बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि बड़ी संख्या में हथकरघा बुनकरों की मृत्यू हुई है। भारत सरकार इस गंभीर समस्या की नियमित समीक्षा कर रही है और राज्य सरकार से भी निरंतर संबंध बनाए हुए है जिससे कि इस समस्या के निदान के लिए और बुनकरों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। मेरे निर्देश पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों के दो दल कुछ दिनों पूर्व ही में कृष्णा, प्रकासम और गुंटूर जिलों में दौरे पर गए। वहां उन्होंने राज्य सरकार के संबद्ध अधिकारियों के साथ मौके पर स्थिति को नजदीक से देखा।

भारत सरकार ने राज्य सरकार से विचार-विमर्श के पश्चात् एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है जिससे आंध्र प्रदेश के जिलों के प्रभावित बुनकरों की दशा में वांछित सुधार लाया जा सके।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए सहमत हो गए हैं की बुनकरों के बकाया भुगतान की आवश्यक धनराशि राज्य सरकार तुरन्त जारी कर देगी। राज्य सरकार ने 5 करोड़ की धनराशि हाल ही में उन्मुक्त की है और 1.75 करोड़ की धनराशि और उन्मुक्त की जा रही है। केन्द्र सरकार ने भी 6 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जनता सब्सिडी के रूप में हाल ही में

[Shri Pragada Kotaiah]

राज्य सरकार को दी है । इस प्रकार उम्मीद है कि बुनकरों के बकाया की समस्या में वांछित सुधार होगा । राज्य सरकार प्रत्येक मृतक बुनकरों के परिवारों को सहायता के रूप में स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से 5 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए भी सहमत हो गई है पांच बुनकरों को एक हजार रुपये की दर से उपभोक्ता ऋण भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा ।

जनता उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बुनकरों को नियमित तथा और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का कोटा उत्पादन के लिए और आबंटित किया है । राज्य सरकार को यह उत्पादन करवाने के लिए 127.50 लाख रुपये की धनराशि विशेष अग्रिम राशि के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी । उम्मीद है कि इसके 24,000 बुनकरों को अतिरिक्त एवं नियमित रोजगार मिलेगा ।

गैर जनता वस्त्रों के उत्पादन में कार्यरत बुनकरों को सहायता के लिए राज्य सरकार की संस्था एकको प्रभावित क्षेत्र के बुनकरों से 2 करोड़ रुपये की धनराशि का अतिरिक्त कपड़ा खरीदेगी । इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 16 लाख रुपये की विशेष विपणन सहायता राज्य सरकार को दी जाएगी । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7,500 बुनकरों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा ।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत 16 नयी सहकारी संस्थाओं का गठन कृष्णा, प्रकासम और गुंटूर जिलों में किया जाएगा । इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 16 लाख रुपये की धनराशि राज्य को इस नयी योजना के तहत दी जाएगी जिससे 800 बुनकरों को दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा ।

बुनकरों को अधिक मूल्य का कपड़ा बनाने की ओर प्रेरित करने के लिए जिससे कि वह हथकरघा पर एक नियमित जीविका प्राप्त कर सकें एक विशेष प्रशिक्षण योजना का आयोजन प्रभावित जिलों में करने का प्रस्ताव है । प्रारंभिक योजना के अंतर्गत 300 बुनकरों को (150 गुंजर में और 150 प्रकासम में) प्रशिक्षण दिया जाएगा । इस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 10.17 लाख रुपये की धनराशि से 300 बुनकरों को 4 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए उत्पादन बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

प्रशिक्षण के दौरान प्रति बुनकर 350 रुपये प्रति माह के साथ-साथ प्रत्येक बुनकर को नए औजार आदि खरीदने के लिए 1,000 रुपये की धनराशि भी दी जाएगी । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हैदराबाद और विजयवाड़ा में स्थित भारत सरकार के बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा संचालित किया जाएगा ।

एक अन्य विशेष योजना के अंतर्गत प्रभावित जिलों के 12,000 बुनकरों का बीमे की सुरक्षा प्रदान की जाएगी प्रत्येक बुनकर को 10,000 रुपये तक का बीमा इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा । इस प्रकार आने वाला 14.4 लाख रुपये का व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर वहन किया जाएगा

बुनकरों को बजट पूर्व की दरों पर सूती धागा उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष प्रयास किया गया है । राष्ट्रीय हथकरघा विकास नगम ने केन्द्र सरकार के निर्देश पर इस क्षेत्र में धागे की आपूर्ति में वृद्धि की है । राज्य सरकार की संस्थाएं भी उपर्युक्त स्थानों पर सूत धागों के वितरण केन्द्र संचालित कर रही हैं । दक्षिण भारतीय मिल संघ (सीमा) के अंतर्गत आने वाली मिलें भी इस बात के लिए सहमत हो गई हैं कि वह आंध्र प्रदेश के बुनकरों को बजट पूर्व के मूल्य पर धागा उपलब्ध करवाएंगी और उन्होंने तदनुसार आपूर्ति प्रारंभ भी कर दी है

मुझे विश्वास है कि इन सभी कार्यों से प्रभावित क्षेत्र के बुनकरों की दशा

वांछित सुधार होगा । मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश में बुनकरों की समस्या की प्रतिदिन समीक्षा कर रही है और अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी ।

SHRI IRAGADA KOTAIAH : Madam Vice-Chairman, at the outset, I thank the Minister for making a statement regarding the steps proposed to be taken or being taken by the State Government with the help of the Centre. But, on the 2nd of September, when two weavers died of starvation at Gullapalli in Guntur district, I have informed of the same to the Prime Minister and also the Minister of Textiles and requested their help to tide over the crisis facing the handloom industry. No doubt, our beloved Prime Minister and also our Minister for Textiles have expressed their sympathy for the dying handloom weavers and said that they would be providing relief to them. But, unfortunately, no relief has come either from the Centre or from the State Government.

Madam Vice-Chairman, what we have been requesting the Central Government is that they should arrange supply of yarn at least at the pre-Budget prices. Madam Vice-Chairman, during the last years, the yarn prices have doubled because of the policy being pursued by the Centre. No doubt, the mills have been direct according to a stipulation that the mills produce hank yarn to the extent of 50 per cent of their marketable yarn. Though the stipulation has been there, in the last one decade the mills are going to courts of law and obtaining stay of the stipulation, and the mills are not actually producing the hank yarn to the required extent. Madam, in89-90, the mills produced 11·000 million Kgs of yarn, but the hank yarn was produced to the extent of 440 million KGs. You can kindly imagine, Madam, it is not 50 per cent, and it is not even 40 per cent also. But, at the same time, the powerlooms are using more than 70 million KGs of hank yarn, though they are not expected to usea hank yarn, according to the Indian Cott on Mills' Federation. But, according to the figures of the Planning Commission, the powerlooms are using annually 120 million Kgs of hank yarn. Then, Madam, the mills and traders are exporting cotton yarn to the extent of 100 million KGs. The Government may come forward and say that they are not exporting hank yarn. And because cone yarn is exported the powerlooms have to purchase hank yarn to the extent required by them, which has two advantages. The price factor is there. And the other is that the cone yarn is not suitable for dyeing purposes. But the hank yarn is more suitable for dyeing purposes. Due to the absence of reservation of handlooms, the powerlooms are producing more of sarees, lungis and other coloured products.

1·00 P.M.

Therefore, hey are using hank to the extent they require hank yarn. Madam, if you are going to deduct 100 million k.g. from powerlooms and 100 million k.g. for exports ultimately the handlooms are having only 200 million or 220 million k.g. of yarn, approximately. But according to the Seventh Plan the handlooms are expected to produce 4,600 million metles of cloth, requiring 460 million k.g. of hank yarn. As against the requirement of 460 million k.g. of yarn, hank yarn is available to handlooms to the extent of 220 million k.g. Therefore, Madam the handlooms are subjected to underemployment for over a period of six months in a year.

Day before yesterday, hon. Minister for textiles gave a reply to one starred question in Lok Sabha and another starred question here. He stated that these deaths of handlooms weavers are not due to starvation. Madam, I would like to read an extract from the *Hindu* a reputed national paper.

> "If you cannot protect the handlooms or provide us with some other employment, please give us endrin so that we can all end our lives en masse rather than struggle with underemployment, poverty, malnutrition, disease and slow death", says a 70-year old handloom weaver, Mr. S. Ramakotaiah of ipurupalam near Chirala. His anguish reflects the economic distress gripping the handloom industry in coastal Andhra where at least 40 weavers died or committed suicide due to abject poverty, starvation or disease in the last two months. Mr. Ramakotaiah questions the prudence of the Central Government permitting export of yarn to the detriment of domestic handlooms.

All newspapers in Andhra Prdesh have extensively published details of the starvation deaths of handloom weavers. Apart from that the *Hindu* and other reputed English dailies also have published articles about the deteriorating situation and asked the Central Government and the State Governments to rush to the rescue of the handloom weavers. Finally, the *Frontline* or the *Hindu* have Reputed an investigation team consisting of an academician, doctor and a lawyer and also press representative. All of them visited almost all the centres in Guntur and Prakasam districts and have come to the conclusion that these deaths are due

[Shri Pragada Kotaiah]

to starvation or starvation related disease. And experts have also gone into the matter in detail and said that these deaths of handloom weavers in Andhra Pradesh are related to starvation or starvation related diseases. They have appeared in detail in Frontline, Dec 6, 1991. But the A. P. Chief Minister while making statement in Delhi said that "they are not starvation deaths. These are deaths due to old age, unemployment or some alcohol." Madam, you are aware that nearly 200 people died after consuming illicit brew in Delhi. Why did the Leiutenant Governor sanctioned Rs. 10,000 each to their deceased families ? It was stated that Govecnments give such payments only to those affected by natural calamities or riots. But here in Delhi, when a large number of people consumed illicit brew and died, the Lieutenant Governor next morning came out with a statement saying that an *ex gratia* payment of Rs. 10,000 would be made to the families. But now, the A.P. Chief Minister's statment hare at Delhi says that he will arrange *ex gratia* payment of Rs. 5000 through some organisations. I am not able to understand as to what those organisations are and how the State government can get money from them. Is it possible ? Here, I would like to quote an instance. In 1951, in Pandillapally in Prakashan (Dt) one pinjala Lingamma after starving for four days, committed suicide. Then, Pandit Jawaharlal Nehru was our beloved Prime Minister. As a weaver-worker, I wrote a letter to Pandit Jawaharlal Nehru informing him of the starvation death in 1951 in the Pandillapally in Prakashan District.He immediately responded to it and sanctioned an *ex. grtia* payment of Rs. 60/- those days. Apart from that, he deputed officers to Madras, because we were then in the composite State of Madras, to get yarn from the southern mills and distribute the yarn in the locality. We were also paid Rs. 2/- to each family for taking up production.

I am not able to understand production-oriented consumption loan. Weavers had asked for interest free consumption loan of at least Rs. 1000/- each to the affected families, to the families in distress. Now the A.P. Chief Minister has coined a term 'Production-cnented consumption loan' to be obtained from the banks. I don't know how he has coined that term and how the banks are going to give the loan. If you approach the bank, you find that they are expected to distribute DIR loans, that is, differential interest rate loan, and they can give to the extent of Rs. 5000/- to the eligible handloom weavers and moratorium on repayment is 18 months and period of repayment is 5 years, and this loan carries only a 4 per cent interest. If the Government is really sincere to help the handloom weavers who are in distress and who are dying not due to any other reason but due to faulty policies of the Government, the Government should have approached the Reserve Bank of India and asked it to direct the nationalised banks and also other commercial banks to advance an amount of Rs. 5000/- for production puposes to each deserving handloom weaver under the DIR loan scheme. But they are expected to advance only 1 per cent of the total advances made by them. If this loan amount is not readily made available to those families, the Government of India will have to subsidise interest on these loans. Government should immedicately arrange distribution of DIR loans at the rate of Rs. 5000/- to the handloom weavers in distress. I have already requested the Chief Minister that he might look into the investigative report in the *Frontline* and know the reality that was responsible for the deaths of weavers. Here, State Handloom Minister has given figures of their dues to Andhra Pradesh State Handloom Weavers Co-operative Society as on 27th of October. The due amount was Rs. 22.18 crores under four heads, to APCO. One is under janata subsidy programme; then against the cloth purchased for 1990 cyclone victims, yarn subsidy and cloth purchased for use of its Consuming Departments. Under these four heads, they owe Rs. 22.18 crores. On the day, there was a meeting of the representatives of the handloom Industry with the Minister on 27th and 28th October at Hyderabad. It was agreed to disburse Rs. 8 crores immediately. When I left the place on 20th November, I was informed by the Primary Weavers Societies that not even a single paisa had been released to the Pimary Weavers Co-operative Societies to whom APCO will have to distribute 22 crores of rupees, with the result that the Primary Weavers Co-operatie Society stopped their production work resulting in the unemployment of a large number of weavers. Further, they had become defaulters and are paying normal and penal interest to the District Co-operative Central Banks on the borrowings obtained from them. This is how things are going on. I appreciate that the Government of India on the 22 nd and the 28th of October had disbursed to the state Rs. 9.12 crores. But when I enquired from the Handlooms Commissioner of Andhra Pradesh, he mentioned that they were yet to receive the money. I do not know why there is a time gap. When the money was released by the Centre on the 22nd and 28th of October, it has not reached the State Government for disbursement to the Primary Weavers Co-operative Societies even in Nov. This is the actual condition of the relief sanctioned by our hon. Minister of Textiles. That is why we have been suggesing to open up production centres.

The deaths of handloom weavers in 1989 in Ipurupalem and Chirla have been referred to. 29 people died. At that time, I was in the hospital. So, I could not look into the matter personally. When that matter was reported to the Government, they opened production centres of the Andhra Pradesh Textiles Development Corporation and provided employment to the families of the victims immediately. Apart from this, they distributed 65 lakhs of rupees as consumption loan to the weavers who were in distress. Our present Chief Minister was then the President of the Andhra Pradesh Congress Committee and I wrote a letter to the then President of the A.P. Congress Committee asking as to why they were not taking up the cause of the handloom weavers in distress. Then, he deputed his Vice-President to go all the way to Ipurupalem. He aprranged a *rasta roko* to get relief for the handloom weavers. Madam, you are in Delhi. What happened on October 2nd ? The weavers who were unemployed brought the *charkha* and placed it on the *samadhi* of Gandhiji at Rajghat. From this, you are imagine the feelings of the handloom weavers. They have surrendered the *charkha* at Rajghat we have *charkha* on our party flag which is the symbol of relief to the villagers, It is understood that the philoisophy behind *charkha* is no more. So they have surendered it. That is why, the Andhra Pradesh andloom weavers protesting against the attitude of the State Government went all the way to the Secretariat in thousands and surrendered their idle handlooms before the Secretariat Government so that the Govt. may place it in the mus. eum and the future generations would know what has become of the handloom, which once had a golorious past.

The hon. Textiles Minister, in one of his letters, said 'We have suspended export of yarn from 21st September'. But immediately, there was a statement by the Ministry of Commerce that exports should be allowed to continue, particularly, by certain sections of the Traders. Therefore, there is no proper co-ordination between the Ministry of Textiles and the Ministry of Commerce. The Ministry of Textiles decides to suspend the export of yarn, but the Ministry of Commerce comes forward and says tha exports should continue and that the suspension should be lifted. For whose benefit ? For the benefit of the capitalists, at the cost of the poor, suffering and starving millions of handloom weavers.

Madam, it is not as ff starvation deaths of handloom weavers are confined to Andhra Pradesh alone. There are starvation deaths in U.P. There are starvation deaths in Kerala. There are starvation deaths in other places. But these have not come to light. No serious notice is there. No non-official agency is ready to take up the cause of the starving masses of handloom weavers. In an article in the 'Economic Times', dated 4th November, it has been categorically stated that handloom weavers in U.P. are dying. There are starvation deaths in several other places also. But no adequate and effective steps are being taken for their relief.

We have been suggesting the stipulation, which is being defied by the mills, for producing hank yarn to the extent of 50 per cent of their marketable yarn should be implemented effietively. Why cannot the Government enact a legislation to enforce the stipulation that mills should produce hank yarn to the extent of 50 per cent and also stabilise their prices, to be fixed by a statutory Stabilisation Committee ?

Madam, you may be knowing that the Handloom Cess Act was enacted in the year 1953. Mr. T.T. Krishnamachari, the then Minister of Commerce and Industry piloted the Bill. While moving the Bill, he said that they would arrange supply of yarn at steady prices, in spite of the market fluctuations operating against them. This was in the year 1953. We are now in 1991. The same thing applies even today. The same thing holds good even today.

'The Hindu' published a news-item on August 8, that there was evasion of excise duties in textiles, to the extent of Rs. 911 crores. I have pointed out that two-thirds of the mill cloth, in the form of cut-pieces, and powerloom cloth produced in the country are sold freely, without being subjected to levy of excise duty. If the Government levies excise duty on the mill cloth and also on the powerloom cloth, which are not being subjected to levy of excise duty, they can earn Rs. 1,000 crores. It is not an ordinary sum. But the Government are not taking any action.

The hon. Textiles Minister, in a letter to me, said that the Government of India had given assistance to the handloom weavers, by removing the excise duty on hank yarn. Perhaps, the Department does not know that the excise duty on hank yearn was removed long back. It is not that it has been done now. It was done in the year 1967. When Shri Morarji Desai was the Deputy Prime Minister and also the Finance Minister, he was presenting his budget on his birthday, on the request made by the Southern States he said that hank yarn was exempted from the levy of excise duty. This Govt. say, we have exempted excise duty on cross reeled yarn also. Who are using

[Shri Pragada Kotaih]

the cross reeled yarn? By waiver of excise duty on cross-reeled yarn you are increasing their competitiveness with the powerlooms who are mostly using cross reeled yarn. Thereby you are hitting more the handloom industry again. But there was no reply from them. That is how the things are moving because the powerloom lobby is a powerful lobby. I am not saying these words. When once we met Indiraji, she said, "Powerloom weavers are having a very powerful lobby, but you have no lobby at all." What kind of lobby can we have ? Are there any representatives of the handloom industry in the Parliament? The interested people of powerlooms are just wandering in the corridors to meet the Parliament Members to work for them. That is how things are going on.

Then the other important raw material is dyes and chemicals. Their prices are increasing, they have doubled or rather trebled also. The green colour was formerly sold for Rs. 500 a k.g. Today it is being sold for Rs. 1500 a k.g. Zari, vat colours, acid colours, naphthol, all are being exported freely to other countries. On the F.O.B value the Government is giving 3 kinds of incentives which comes to 42 per cent. The one is in the form of cash compensatory support, the other is import entitlement and the third is drawbacks of Taxes, total 42 per cent is being allowed on the export of vat naphthol and acid dyes. Who are actually receiving them ? They are only 8 or 9 manufacturers who are producing these dyes and chemicals. So, our policies are intended only for the benefit of capitalists and not for the poor handloom weavers. Did they make any arrangement for supply of dyes and chemicals to weavers. They say that they have asked the National Handloom Development Corporation at Lucknow to purchase dyes and chemicals and supply them to the primary weavers' societies. I am giving an example. My society at Niddubrolu sent the money to the Corporation which is having its branch at Hyderabad. Nothing came for four to five months. Ultimately I had to make a complaint not only to the Development Commissioner here but also to the State Development Commissioner. Finally the dyes and chemicals had to be purchased in the open market. Is it possible for the National Handloom Development Corporation to purchase dyes and chemicals at stable prices from these capitalist manufacturers ?

With regard to yarn our Minister was saying, in his letter dated 21 Oct, 1991 that we have approached the SIMA, that is South India Mill-owners Associations and the Northern India Millowners Association and that they have agreed to supply yarn at the pre-budget price. Let the Government show one instance where this capitalists of textile mills had helped the handloom weavers in times of crisis. They are trying to exploit the handloom weavers to the maximum extent possible. They N.H.D.C. has already opened depots at Palakol, Bhattiprolu, Chirala and Mangalagiri. What was the price of the yarn offered for sale ? The price for 40s, 10 lbs bundle, was offered at Rs. 274 while in the open market it was being offered for Rs. 262.

This we informed the Government. What did they do ?

Madam, it is no good depending upon the capitalist sector. While intending to provide benefits to the poorer sections, the Government will have to take firm action and procure the yarn from the mills. They must use their special powers. In the past, when Pandit Jawaharlal Nehru was there, when Andhra Kesari Prakasam Pantulu was there, when Rajagopalachari was there, when we reported our difficulties to them, they would send their officers to break open the godowns, get the yarn in lorries and supply it to the handloom weavers. The same powers could not be used by the present Government to help the handloom weavers. So there is no use depending upon the Textile Mills Associations.

On exports of yarn and on exports of dyes and chemicals, they are paying three kinds of incentives. Why can't they take a portion of it and utilize it to reduce the prices of yarn ? The wonderful thing is, the Handloom Cess Act, for the purpose of levying three paise per yard of mill cloth was there in 1953 to provide funds for the development of the handloom industry, but that Act was repealed. Why was it repealed ? For what purpose? Did you achieve the object of supplying yarn at steady prices in times of fluctuation operating against the interests of the handloom weavers ? No. Then why was the Act repealed ? For whose benefit was that Act repealed ? Like that they can levy excise duty on mill cloth and power loom cloth which are sold freely in the market and pay some drawbacks to the handloom weavers.

We are producing exportable products. We are paying taxes on the raw materials. But, ultimately, to whom are you giving the drawtacks ? To the exporters. They have nothing to do with production ? We are producers. We purchase yarn in the market, we purchase dyes and chemicals in the market. We are paying excise duty, we are paving sales tax and other duties, but the drawbacks are given to the exporters and there is no

share for the producers. Can't they give a share to the handloom weavers who are responsible for paying different kinds of taxes on different raw materials and ultimately producing exportable products for the benefit of the country ? Is it entirely for the benefit of the exporters only ? The Govt. are not considering that. I am not able to understand why they are not able to do that.

About reservations, Madam, it is a very long story. Immediately after Independence, in 1948, an Industrial Conference was held. Pandit Jawaharlal Nehru thought of appointing an All-India Cottage Industries Board under the chairmanship of Kamaladevi Chattopadhyaya. A Standing Handlooms Committee was also appointed under the chairmanship of Prof. N. G. Ranga, the veteran leader of the Congress and who is an age-old leader of the Congress Party also. Then they had decided that sarees and dhotis and certain other things had to be reserved for handlooms. When that resolution was presented, Shyama Prasad Mookerji, the then Industries Minister in the Cabinet of Pandit Jawaharlal Nehru, could not immediately accept it. By the evening the might have consulted Pandit Jawaharlal Nehru and, in the evening, the then Industries Secretary, S.A. Venkataraman sent a word to Prof. Ranga and said, "you select two of your representatives and the Government will select two of the mills' representatives, and the Textiles Commissioner will be the Chairman of the Committee and they will reserve certain items for the protection of handlooms." That was done on 30th April 1950. For the first time reservations had been made for handlooms under the provisions of the Essential Commodities act. But, unfortunately, during the last 40 years they continue to be on paper only. After repeated representations to the Government, the former Prime Minister V.P. Singh, who was then Commerce Minister in Rajiv Gandhi's Government, introduced a Bill for reserving certain items of cloth to handlooms. That was done in 1985, and in 1986 a notification was issued reserving certain items for the handloom industry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : Mr. Kotaiah, one minute. You continue after lunch.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : After lunch ten minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : You continue after lunch, at 2·30 p.m.

The House is now adjourned for lunch till 2·30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty four minutes past two of the clock. The Vice- Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE —Contd

THE PLIGHT OF HANDLOOM WEAVERS OF THE STATE OF ANDHRA PRADESH RESULTING IN STARVATION DEATHS OF MANY OF THEM AND THE ACTION TAKEN BY GOVERNMENT IN REGARD-THERETO—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : Mr. Pragada Kotaiah, I think you have already covered the main points. Now, please try to conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : The measures suggested by the hon. Minister of Textiles are only palliatives. They are not going to solve the problems of the handloom weavers. Handloom weaving Industry provides employment to the villagers all over the country. In Chirala, Andhra Pradesh, most of the looms produce exportable varieties, that is, Madras handkerchiefs, Madras checks and lungis. These are the three varieties of cloth that are produced in Chirala where there are 20,000 handloom weavers. Since the price of yarn has gone up from August onwards. the producers in the private sector have either slowed down or stopped giving work to the majority of the handloom weavers living there. Though the Government is very particular that 60 per cent of the handlooms shall be brought into the cooperative sector, but so far the Government could bring only one-third of the 40 lakhs of the handlooms. That means 13 lakhs of looms are in the cooperative sector and they are providing employment only to half of them. On the one hand, they said that the handloom weavers will be brought into the cooperative sector but on the other hand, they are setting up Handloom Development Corporations. May I know from the Minister wehether the Government is interested in the setting up of Handloom Development Corporations managed by officials or whether they are interested in the setting up of cooperatives, as promised by them to bring handloom weavers gradually into the cooperative sector and provide more employment opportunities.

[Shri Pragada Kotaiah

Apart from this, there is another class of people generally known as master-weavers, that is, producers in the private sector. In all other sectors, whether he is a member of the cooperative society or whether he is a member of the corporation, all types of assistance are being given, For instance, agriculturists are getting fertilizers at subsidised prices. Similarly, all other social welfare measures are being extended to the people whether they are in the cooperative sector or not. Two-thirds of the handlooms are still in the hands of the master-weavers. They are providing employment to all of them. But there is no provision of working capital for them. There is no provision to suply raw materials to them. There is no provision for marketing their, products. How long should they cotinue like this ? Avadhan Committee recommended several years back provision of working capital of the handloom producers in the private sector and marketing of their finished products. But we do not know what has happened to that report. Perhaps, it is in the cold storage. If the Government is interested in the cooperative sector or in the corporation or any other sector. they should spell it out. How are they going to help the corporations, cooperatives and the producers in the private sector?

Sir. coming to the point of yarn, it is not good to ask the mill-owners to supply the yarn. It is below the dignity of this Government. They should not take the yarn from the mill-owers' association. I hope under the dynamic and deicated leadership of our Prime Minister, he would see that the yarn is supplied to the handloom weavers at the pre-budget prices. They should order them if they have powers. Otherwise, they will have to seek powers under a legislation and procure yarn from the mills at stabilised prices.. What did Mr T.T. Krishnamachari, in the year 1953, intorducing the Handloom Cess Bill, say ? "The Government shall supply yarn at stead prices in spite of the market fluctuations operating against them". That has been there till now. Therefore, I request the Government to enact a legislation to enforce the stipulation that the mills in the private sector, the NTC and also the cooperatives sector should procure hank yarn, standard yarn, not bad yarn to the extent of 50 per cent and that yarn should be procured by the NHDC at the Centre and the State apex societies at stabilised prices, to be stabilised by £utry stabilis ation committee. Sir, the Government has got a provision of Rs. 6 crores in the Budget in the Textiles Ministry. For what purpose? To stabilise cotton prices. Since at the present juncture, that money may be appropriated mainly to the handloom sector and yarn may be supplied at subsidised prices with the grant of Rs. 6 crores proposed to be spent on cotton because they are already getting higher prices. That is what we understand. That money should be diverted. If it is not possible, the Govetment can provide at least Rs. 10 crores as an immediate measure of relief and provide subsidised yarn to handloom weaver through NHDC and the State apex societies for which they will have to allow, empower and strengthen the NHDC and the State apex societies on the lines of the FCI.

Coming to the reservation point, the most important point, what do legal experts say? The 1985 Act was stayed by the Supreme Court and the notification issued under the Act was also stayed by the Supreme Court in the year 1986. During the past five years, the Government was sleeping over the decision, the Supreme Court order. They did not make any effort to get the stays vacated. Therefore, Sir, the reservations said to have been made for handloom continue on paper. Under the present circumstances, what the Government shall do? The legal opinion is like this:

"The proposed inclusion of the Handloom (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 in the Ninth Schedule does not put an end to the litigation because while the Act will be beyond the scope of judicial review, the order issued under section 3 of the Act, by which the actual reservation of articles for handlooms is made, cannot be protected from litigation. It is, therefore, suggested that the Act, 1985 may be so amended as to include a separate section specifying the main articles of reservation for handlooms such as sarees, coloured, red, check and tie and dye dhotis and lungis, bedsheets, woven from cotton and natural silk so that the validity of such reservation made through the Act that is, included in the Ninth Schedule could not be questioned in any court of law. In regard to the other minor articles such as shirting towels, etc., orders of reservation for handlooms can be issued from time to time under section 3 of the Act, 1985 as per the recommendations of the Advisory Committee to be appointed under section 4. Such orders of reservations can, of course, be challenged in courts of law but the mischief caused will be minimal.

It is, therefore, earnestly urged that a bill to amend suitably the Hand looms (Reservation of Acticles for Production) Act, 1985 may be introduced in the Parliament and the amended Act included in the Ninth Schedule through a Constitution Amendment Bill. The suggested legislation will enable the Government to effectively enforce the legislation and the reservations made to handlooms under the provisions of the Act."

The forty-years old policy decision of protecting the handloom industry and stop the gradual decline that is occurring in the employment opportunities in the handloom industry will be implemented for the benefit of handloms. Sir, the Govrnment of India will have to spell out their textile policy first. See, during the Seventh Plan, when they wanted the production of cloth to the extent of only (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude.

श्री छोटूभाई पटेल (गुजरात) : गरीबों की आवाज है इनको ज्यादा टाइम दे दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): He has already spoken enough. Please try to conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: There are already mills with 2,10,000 looms. They are capable of producing 5,000 million metres of cloth. There are 11,00,000 powerlooms operating in the country, capable of producing 20,000 million metres of cloth. Forty lakh handlooms when provided employment throughout the year, are capable of producing 6,000 million metres of cloth. The total comes to 31,000 million metres of cloth as against the total requirement of 15,000 million metres of cloth. Therefore, the Government will have to spell out specifically what their future policy is. Under the liberalised Industrial Policy, the capitalists anywhere in the country can set up powerlooms without obtaining any licence or without paying any licence fees to anybody. Therefore, what shall be the policy under the liberalised Industrial Policy? Therefore, the Government will have to spell out the textile policy so as to provide full and continuous employment to the handloom weavers. We are spending crores and crores of rupees in the name of generation of employment. I am living in Ponnur Municipality. In Ponnur Municipality, the Government has given Rs. 4 lakhs under the Jawahar Rozgar Yojana, that is subsidy of Rs. 12 lakhs had been obtained from the bank and about 240 people have been given loans to the extent of Rs. 16 lakhs. But is there any evaluation to ensure whether they have properly utilised the money? Has any employment been generated? I raised this matter in the bankers' meeting to know whether they have any evaluation machinery to know that the amount spent in the name of generation of employment is being properly utilised. There was no reply from the bankers. Therefore, the Government will have to consider that thing, Sir. The Government is consuming cloth worth hundreds of crores of rupees. During the Second World War we were in Madras. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Kotaiah, I know you are very much associated with the subject and you can speak for hours together. But you shall have to conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, I will conclude within ten minutes. I would like to say a few words on this. We were producing *Do-Suty* cloth, Magiri, drills. bedsheets, napkins, all these varieties. The Defence Department had placed an order with the Madras Provincial Handloom Weavers Cooperative Society and we had produced them because then the mills were not in a position to produce all defence requirements cloth. They had entrusted the production to the weavers' coopertive. Why can't we adopt a similar policy now? There are several consuming departments. What I say, Sir, is that we are not profiteers; we are not exprters; we are only workers. Let the Government give yarn. Let the Government give chemicals, pay minimum wages for producing the type of cloth which they want and give some 70 per cent margin to the society which takes up the production. Therefore, Sir, we are requesting that the Government should select such other varieties that can be conveniently and profitably produced by handlooms on conversion basis. We don't want single tender system, price system, this and that as we are not in possession of the raw-material.

Therefore, you should provide employment to us by producing your own varieties on conversion basis.

With regard to rehabilitation, what I want to submit is that thousands of handloom weavers have lost their employment due to floods and other things. Their looms have been lost, their yarn has been lost, their houses have collapsed. The Government has spent 63 crores of rupees for the rehabilitation of mill workers in the closed mills during the last five years When I put a question to the Government, they said that not a single pie had been spent for the rehabilitation of hand loom-weavers. Is this the social justice we are aiming at ? Is this the social justice

[Shri Pragada Kotaiah]

that for a few tthousands of workers in the mills you have spent 63 crores of rupees, but for the rehabilitation of handloom-weavers suffering because of floods or cyclones or rains you did not spend a single pie ? This is how the Governments are functioning, Sir! Many people say that you are having an outdated loom. Sir, I am a traditional handloom weaver. In the golden days we had old throw-shuttle looms. Nowadays we are having fly-shuttle looms. In the past we had travelling warping system. We are now having roller-warping system. We are having dobbies, Jacquards draw-boy harness. With all the improved implements we are capable of producing. We, sitting in the rural parts of the country are able to produce cloth required by persons living in America, in England, in Germany. You can understand that these skills would have expired but for us. Our cottages are the institutes. The Government has not set up any institute to train the handloom-weavers. Our cottage is the institute. The implements owned by our forefathers are the implements for training. Our forefathers and mothers are the instructors to give necessary skill. We are producing the cloth required by the foreigners also. In the olden days we requi red two to three persons to produce a solid water effect. Nowadays we don't require two, three people. We have arranged the mechanism in such a way that all the three shuttles can travel in the same shed to the extent required and we are producing solid border effect. Sir, kindly see that we are alive in this country, not only in the interest of the handloom weavers but in the interest of the country also.

In conclusion I would like to say one word only. In 1934, the then Governor-General, perhaps Lord Bentinck, in a report to the British Parliament stated that all the burial grounds in the five lakh villags of India had turned white because of the skeletons spread over them. Why ? Because of the atrocities of the East India Company. Our Government wedded to the welfare of the weaker sections of society and the socialist pattern of society shall immediately come forward to help them. It should not depend upon the capitalists. It is very unfortunate that the administrative machinery is not having a positive approach. I would urge the administrative machinery to have a positive approach to help the weaker sections of society. It should not have a negative approach. The administrative mahinery should not come in the way of helping poorer sections of people. The administrative machinery should help the helpless and helpless sections of society. I don't know why they can't come and say, "Help is here." We have modernised looms, But we cannot shout slogans and make noise, but this hon. House can certainly consider and bring pressure upon the Government to help the helpless handloom weavers of this country.

SHRI K. K. VEERAPPAN (Tamil Nadu) : Sir, I associate myself with the views expressed by my friend, Mr. Kotaiah. I request the Central Government to take whatever immeidiate action it deems fit and provide all help to the suffering handloom-weavers.

SHRI CHHOTUBHAI PATEL : Mr. Vice-Chairman, Sir, I also want to associate myself with Mr. Pragada Kotaiah. (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : No. He has already spoken and the Minister is here. He has taken note of it.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, there are three sectors in the textile industry. There is mill sector ; there is powerloom sector; there is handloom sector. For the last so many years there has been overlapping of interests and even conflict among these sectors and the Government has been really pressed by all these sectors one time or the other. I feel that the textile polices announced earlier may, perhaps, require a second look on the part of the Government in view of the various problems that have come up. The earlier policies and strategies followed by the Government do not seem to have resolved all the critical issues confronting the textile industry as such. Among these three sectors, the weaker sector is, naturally and obviously the handloom sector. This sector has been employing a large number of people. It has got a great employment potential and it has got a history of its own.

At the present moment, the handloom industry is facing various problems of which two or three are critical. One is the prices of yearn and other materials such as chemicals, dyes, zaries, etc. Second is the availability of yarn and other materials. They are not easily available to the handloom sector. Besides this, the handloom sector is also faced with marketing of the products. They do not have institutional finance. They do not have institutions strong enough to take care of thier day-to-day problem and the co-operatives in the handloom sector are weak. They are not very strong.

3.00 P.M.

All these things have added to the present critical situation that prevails in the handloom sector. I feel the Governmen has to take a long term view to sola

their basic problem. The problem faced by these three sectors have to be clearly demarcated. This demarcation is already therre, but of late the powerloom sector is encroaching the territory of the handloom sector. The weavers of the handloom sector have become more vulnerable. Sir, the Government some time back decided to export cotton. I am totally against this. When the cotton itself is in short supply, when the yearn is not available to the weavers, the export of cotton or cotton yarn is definitely against the interest of the handloom weavers. I am aware of the difficulties involved when you decide to export. wnce a commitment is made we have to honour it. That is the difficulty. But I only wish to suggest that with the experience tha we had in the past we know the product trends of cotton and cotton yarn, the capacity, and keeping in view all these things-we should make a rational allocation so that domestic requirements are also met. By all means you can export, we do require foreign exchange, but it should be subject to domestic demand. The domestic market has to be taken care of. The handloom industry is in dire straits in every part of the country, but it is particularly so in the State of Andhra Pradesh. More the situation is very critical I am not going into the question whether there have been starvation deaths because the handloom weavers are not getting any work. But the fact remains that there have been deaths of handloom weavers, not one or two, but nearly 100 or even more than 100. They have died and I am told in Prakasam district, there have been suicides also, the reason being the handloom industries do not get adequate supply of yarn, and the Government is rath3r indifferent and callous in Andhra Pradesh in regard to their demands. In Karnataka from where I coem, there is a similar situation. A similar situation prevails elsewhere alsp. But it is acute in Andhra Pradesh. I plead with the Government that they sould evolve a preagmatic policy whereby the powerloom sector does not encroach upon the handloom sector. In other words, the powerloom sector should not enter the territory of the handloom sector. There should be a division of sectors and this division has got to be maintained as far as possible and we have to give more help, more assistance, to the most vulnerable sections of the textile area, that is,the handloo m sector.

Sir, we have been permitting the export of yarn also and I think a second look is necessary now as to whether some regulation or postponement of export of yarn can be done so that the needs of the handloom sector may be met fully and adequately.

Finally, one word about the organizational or institutional set-up. It is weak, as I said earlier, and I think some thought should be given to thetuestion of strengthen'ng the co-operatives in the handloom sector. Individual weavers will not be in a position to compete ith the powerloom sector because powerloom is more powerful. To meet this challenge from the powerloom sector I do not want to stifle the powerlooms the handloom sector should be strengthened and the only way is to give them institutional advantage over the powerloom sector and the co-operatives have got to be strengthened in this regard and there has got to be adequate finance. I am not pleading for subsidy here. But I am pleading for tax concesions for the handloom sector. I think the Government is ging into this question as to the ways in which there can be tax reliefs so that the handloom cloth can be mde more competitive with the cloth produced by the powerlooms and the nills. Sometime past, we had thought of an approach whereby those materials, those fabrics, that could be manufactured by the handloom er sector would not at all be given to the other sectors. We have to find out what that division can be brought about now. I would like him to think about it. It is not being implemented now, I think Sometime in the late 'seventies it was done and it was given up. Such of those fabrics as can be successfully manufactured by the handloom sector should be reserved for the handlooms only. I am not going into the question of including the Act in the Ninth Schedule of the Constitution and my friend has already touched upon that aspect. Bu I would say that every step has got to be taken to strengthen the handloom sector.

Then, Sir, the training programme has got to be strengthened. Sir, this is a competitive world and there is no use going back to the 'forties or the 'fifties. The handloom sector has also got to compete with the other sectors. Therefore, I would like the handloom weavers to be trained properly. There should be modernisation. There should be improvements in the techniques, improvements in the looms, improvement in the marketing techniques and improvements in every field. So, modernisation should not be shelved. If we do it, I think, the handloom sector will die a natural death. The question is not of solving one or two problems of the handloom sector. The problem before us is its survival and whether the handloom sector can survive in the modern competitive world where modern technology operates ruthlessly. Therefore, I say that the handloom sector should also modernise itself and should become effective and competent. Thank you, Sir.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Thank you, Sir, for giving me

(Shri A. G. Kulkarani)
me an opportunity to participate in a very useful and constructive discussion initiated by my friend, Mr. Pragada Kotaiah. Mr. Vice-Chairman, Sir, I agree with the emotional appeal which my old friend Pragada Kotaiah has made. I am one with him, and I have got all the sympathies for the handloom weavers in their difficulties.

Having said so, Mr. Vice-Chairman, Sir, I appeal to the House and to this Government that once for all the Government must go into the intricacies and the nitty-gritty problems of the textile industry as such.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in 1985, the Government announced a textile policy, and the expertise was included in that Committee when Mr. Ram Niwas Mirdha and his predecessor were there in charge of the Ministry. I had various discussions at various levels at that time. Mr. Vice-Chairman, Sir, as my friend Mr. Gurupadaswamy has just now said, there is no use invoking the history of this country's freedom struggle and what Gandhi, Nehru and all other leaders have said. We are in the present world where only the technology counts. And if one has to live in the liberalised economy which the Prime Minister and his Government has initiated, one has to definitely go in for technological innovations in every sector. Mr. Vice-Chairman, Sir, I do assert that after 1989, during the interregnum of the two short Governments of Mr. V.P. Singh and Mr. Chandra Shekhar, there was a total mess of the textile policy. During the later period of Rajiv Gandhi, as there was a demand that some review should be taken, the Abid Hussain Committee was appointed. The Abid Hussain Committee was appointed to find out that the ailment is of the handloom industry because of the new textile policy,. Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very sorry to say that in these two periods of various Governments, the textile policy was in a mess. But, now it is incumbent upon the Government of Mr. Narsimha Rao and my party that when we have liberalised the economy, when we are inviting the technology into this country to create more economic resources and more employment opportunities, there must be some innovation in the textile policy itself. And much water has flown after the recomendations of tht Abid Hussain Committee also. Sir, there is no textile policy at present. The textile policy is manifest only in the failure of all the sectors whether it is handoloom or powerloom or organised mill sector, and all are sufferers, and all are at the end of suffering. Mr. Vice-Chairman, political pressure are being brought on the Government to mend and dent the policy and find out which sector or which vested interest is benefited from the policy which the Government may announce. When I say that political pressures are being built up, my friends who are talking on handloom will sympathise with that. There is another sector which is pressurising the Government to export cotton. I don't understand how two contradictory things can produce one better result. Farmers want cotton to be exported. Handloom weavers want yarn at cheaper price. How can these two things happen? They cannot happen. Mr. Vice-Chairman, I quote from a different paper prepared by our organisation, cooperative organisation. "The price of cotton from October, 1990 to the end of August, 1991, has increased by 60 to 100 per cent. Yarn price--cotton being the main raw material-increased by 14 to 25 per cent". So, I pleased with the Minister , Shri Ashok Gehlot, and I wrote him a letter that in this policy the Government has created 100 per cent exporting units. Then the Government wanted aggressive exports to earn foreign exchange. Suddenly, you closed down the channel of exports where contracts were made. Mr. Vice-Chairman, I have a paper dated 9 October, 1991 when the Textiles Secretary was addressed in the matter who held a meeting on 7th October, Sir, the apex organisation, Indian cotton Mills Federation has agreed and they have said, the industry has agreed to make available two nominees, Development Commissioner of Handlooms and the Director, Handlooms for Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Uttar Pradesh and NHDC. How has yarn been made available at pre-budget price? Here is the Abid Hussain Committee Report, which says, it has gone into the difficulties of the handloom weavers. They say that the major problem facing handlooms is the hank yarn. At present 40 per cent of the production is hank yarn. It is not that it is not producing any hank yarn. The difficulty -- Mr. Kotaiah has rightly pointed out --is the organisational weakness in this sector. I am as much connected with handloom and powerloom as Mr. Kotaiah is connected. He and I were President and Vice-President respectively, of the cooperative organisation for 17 years. He was Vice-President and I was President. We all along insisted on the Government for a policy on textiles.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY : Did you quarrel?

SHRI A.G. KULKARNI : No. Shri Pragada Kotaiah is a dedicated person. He is a Gandhian and I am proud of him. He has his views ; I have my own views. When he came to me with some letter, I said : 'Why are you involving me ? I represent a different sector". The point is, I am a person who believes in the new technology, who believes in

exports, who believes in bringing more money in this country. That is why I appeal to the entire House. Don't be emotional ; be rational and pragmatic. The prices I quoted are authorised prices. Cotton prices in this country are 30 to 35 per cent above the international prices ..(*Interruptions*). This is an example of emotional politicking. Probably he has some relative who is a farmer and he wants cotton to be exported and poor Mr. Gehlot is unnecessarily pressurised and pinched. What I wanted to say is, even if you want to solve Mr. Pragata's problem or anybody's problem, you have to evolve a rational policy, whether handloom or power loom, whether it grow or does not grow, because this sector is growing and is growing on its on strength. It does not require any body's *meharbani* either of the Government or the bank. It is growing on its own strength. Even farmers are producing and they do not require assistance from you for growing grapes or mangoes. We grow grapes which are exported to France, and we get ten times more price than what the Government can get. This is a new technological advent. So, for Heaven's sake, I request, don't get yourself involved into these conflicting views; you should have a rational textile policy where the interest of the cotton farmers has to be protected, because unless the cotton grower is protected, handloom weaver cannot be protected whatever you may wish. We may spend thousands of crores on subsidy to the handloom weavers but we will have to give this subsidy for the entire life which we may not be able to do. So, I would only say that the Government has no textile policy. Please evolve a textile policy which is rational.

With regard to cotton exports, here is the Agriculture Ministry also at the throat of Mr. Gehlot.

मि. गहलोत की हालत बहुत खराब हो गयी है । बलराम जी आते हैं, उनका गला पकड़ते हैं और कहते हैं कि कॉटन एक्सपोर्ट करो । प्रागदा कोटैया आते हैं, वह बोलते हैं कि यार्न की प्राइस नीचे लाओ । कहां से करेंगे ? यह उनके बस में नहीं है ।

So, evolve a policy as a Government policy where value-added is the only crition for textile exports. By exporting cotton, what are you going to do? You know I am a cotton yarn exporter from the co-operative spinning mills. I am not a private sector man. We have got formidable 30 per cent production in this country through co-operative sector. But the difficulty of m friend, Mr. Pragada Kotaiah is tha y Andhra is lacking in co-operative infrarstructure while Tamil Nadu has got a formidable co-operative infrastructure. So, such problems do not arise there, and it was due to Mr. Venkataraman, who is our President, that a rational policy was evolved in Tamil Nadu. So, it is very necessary that a textile policy is evolved which is rational and an aggressive export policy. We have built up export during the last 15 years by exporting cotton yarn. Southern mills in Tamil Nadu are the best cotton yarn producers and they are exporting hank yarn which is never exported.

गलतफहमी मत करना । यार्न का कभी एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं । गवर्नमेंट परमीशन देता नहीं और होता ही नहीं है ।

So, don't go by emotions. What I to say is that the policy should be that the handloom weavers get the yarn of 40s. Here is an organisation and when we talked with that organisation, they said, "Please give us one man who will lift all the yarn". But there are difficulties because in Uttar Pradesh, co-operative infrastructure is not there. Also, in Andhra Pradesh, there is no co-operative infrastructure. But Tamil Nadu, Karnataka and Orrisa have a viable co-operative infrastucture. I would request Mr. Gehlot to sustain the exports which we had buit built up. You have now removed all the restrictions except between 40s and 60s. But this is also irrelevant, irrational and uncalled for. Another factor you have to take into consideration is that in the East European community, bilateral trade has been wiped off because every communist country has closed its door. They have no money to purchase anything in bilateral trade. So we can sell yarn only to Japan, Korea, Australia, Hong Kong, Taiwan and Europe. They require the yarn between 20s and 60s. By removing this small gap, 40s and 60s, the yarn which is destained for export and where commintments have been made is piled up at Bombay Port. This is worth 50 crores of rupees, from co-operatives alone. I would plead with you that this problem and Mr. Pragada's problem are two diffrerent problems. This is the yarn which is meant for export, for which contracts had been entered into. So, don't disturb the export channel. We took 10 years to build up the export. This is a very important aspect. Unless you satisfy the cotton growers, the handloom weavers' problenms are not going to be solved, whatever Mr. Pragada or Mr. Sivaji or I may say. Mr.. Pragada wanted yarn at a cheaper rate. I request the Government to evolve a new policy.

(Shri A. G. Kulkarni)

There is no necessity for a review at all. Every material is with your Ministry. For heaven's sake, the Government should have.... (*Interruptions*)

SHRI PRAGADA KOTAIAH : It is not the problem of Pragada alone. It is the problem of millions of people. They have to live. They are not to die.

SHRI A.G. KULKARNI : I understand that it is the problem of millions. But farmers are in crores.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : They are very powerful and vocal. The helpless are the handloom weavers.

SHRI A.G. KULKARNI : Please permit Kotaiah to fight with Sivaji.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : I can't permit anybody to fight here in the House. I shall only request you to conclude.

SHRI A.G. KULKARNI : I am concluding now. I only plead that the Government must have a rational policy and have a value-added export. Unless they are permitted to export that small portion of 40s and 60s, crores of rupees would only be thrown into dustbins and water. Since exports have been commited and bilateral trade has laready been finished, for heaven's sake, do this in the interest of the country and in the interest of your Government's policy of liberalising the economy and the invention and advent of technology.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I draw the attention of the Government, through you, to the sad plight, the pathetic condition, and the suffering of the millions of handloom weavers. I share the concern expressed by Mr. Pragada Kotaiah regarding the starvation deaths....

SHRI A.G. KULKARNI : I also wept, my dear.

SHRI V. GOPALSAMY : I share his concern regarding the starvation deaths which took place in the State of Andhra Pradesh. Seventy-three handloom weavers diod of starvation, died of hunger. Of them, seven committed suicide. It is a story of desolation and despair, and of death. 'Reports of starvation' deaths and of suicides triggered by sheer desperation are currently filtering out of the area with disquieting regularity.' This is what has been reported in the 'Frontline'. An investigation team from the 'Front line' visted the State of Andhra Pradesh and, in their report, they have said : '....the current situation in the weaving communities of Guntur and Prakasam districts is one of sharply deteriorating conditions of life. Many weavers and their families, already existing below the threshold of poverty, seem posied to descend beyond the point of physical survival unless intervention is decisive, large-scale and imediate'. Sir, I can quota the agonised cry of the handloom weavers, which appeared in the 'Indian Express'. One weaver said—I quote :

> "If you cannot protect the handlooms of provide us with some other employment, please give us endrin-poison -
>
> so that we can all end our lives *en masse* rather than struggle with underemployment, poverty, malnutrition, disease and slow death, says a seventy-year old handloom weaver, Mr. S. Ramakotaiah of Ipurupalem near Chirala".

Sir, after many years of Independence, this is the position. One shudders to read the news that people die of hunger and starvation. After implmentation of so many Five-Year Plans, after spending cores of rupees, people of die of hunger and starvation. It is not happneing in Ethiopia. It is happeing in India.

What are the reason for this problem? This is a problem of seventeen million people who are engaged in this industry in the country. Seventeen million. The Father of the Nation rightly said that 'the handloom weavers in the country are bleaching with their own blood and tear'. From different directions, the handloom weavers are persecuted. The sufferings of the handloom weavers are mainly due to the hike in the price of yarn, the non-availability of yarn, and the impossiblity of selling the cloth they weave. These are the three main problems. Sir, following the export of 700 million kg. of yarn till September this year—as against 40 million kg. in 1988, 62 million kg. in 1989, and 90 million kg. in 1990-- the yarn price registered a steep hike after the Budget presentation. The price of yarn—40 count—rose from Rs. 125 in 1985, to Rs. 250 in 1990, and jumped to Rs. 330, for a bunlde of 4.5 kg., in July this year. Similarly, the price of 80 count yarn increased from Rs. 550 a bundle in December last year to Rs. 700 in July this year. The increase in yarn price pushed up the price of a handloom lungi by Rs, 6 and a Zari Sari by Rs. 20, The handloom Industry could not absorb the price rise immediately owing to stiff competition from the powerlooms. While a zari sari produced on handloom costs Rs. 160, the powerlooms are flooding the market with printed saris for just Rs. 90. Thus the handlooms already handicapped on the price front vis-a-vis the powerlooms, find it difficult to increase the price.

Meanwhile, the glut in the market has compelled the master-weavers to reduce their production by 30 to 50 per cent. This has made some looms idle or has reduced their work. Consequently, the income of the hapless handloom weaver has dwindled from Rs. 500 to Rs. 300 a month at a time when the prices of all essential commodities like rice, dhal and edible oil are skyrocketing.

Sir, stocks are piling up forcing the weaver to reduce his production. Here again I quote the tragic story of another couple. An aged couple used to live by weaving four lengths of janata dhotis to earn Rs. 240 a month in Bhattiprolu village. When the husband could not weave due to failing eye-sight, the wife, Nagamalleswary aged 58, took upon herself the task and wove three lengths to earn Rs. 180 a month. But following the glut in the market, the master weaver gave her work only for two lengths reducing her income to Rs. 130. Despite weaving for 10 hours a day, she could not provide one meal a day to the family. Distressed and malnourished, she died. As life should move on without wife or eyesight, her husband, Mr. Venkataramaiah, aged 65, now weaves dhotis on his loom to keep hunger at bay.

Sir, there are many stories, heart-rending stories. Here is a case when the wife of a weaver suffered an abortion. He had to sell away his loom to meet the medical expenses of Rs. 1000. He borrowed a loom for Rs. 30 a month and continued his vocation. But following the glut, his income dwindled and to look after his sick wife he pledged the yarn supplied by the master weaver. When the master-weaver coerced him to produce the cloth, he committed suicide.

Sir, it is high time for the Government to come to the rescue of these people. Again the Frontline's investigation team has reported that unless it comes to their rescue, the life of the weavers will become more miserable. There are an estimated 3.5 million handlooms in the country, supporting roughly 17 million people. Of this, Andhra Pradesh has an estimated 525,000 handlooms on which some 2.5 million people subsist. But, Sir, the State of Tamil Nadu has got the highest number of handlooms, 5,56,000 looms where about 3 million people are engaged in handloom weaving. Mr. Kulkarni has correctly stated about Tamil Nadu. So, I would request the Government, through you, Sir, to persuade the Andhra Government. The same party is ruling both at the Centre and in the State. They should make a thorough study to see what steps have been taken in Tamil Nadu in this sector to protect the handloom weaver. Sir, even three-four decades ago the evolutionary leader of social justice, Periyar, revered leader Anna and my mentor and leader Dr. Karunanidhi, all these leaders of the Dravidian movement, when there was a glut in the market, when crisis was faced by the handloom weavers, when the weavers could not sell their stocks, they carried on their own shoulders in the streets to sell the cloth which gave a tremendous fillip to the people to purchase. My leader, Dr. Kalaignar, did the same thing in 1973 when there was a crisis again when the weavers could not sell the cloth they had woven.

Sir, Mr. Kulkarni has referred to co-operative spinning mills. There are 18 cooperative spinning mills in the State of Tamil Nadu. Of course, there were losses before we came to power, just two years back. When we came to power, the spiniing mills were incurring losses to the tune of Rs. 35 crores, but because certain steps were taken by us, the same spiniing mills started earning profits. Sir, through the cooperative spinning mills we supplied yarn to the weavers' cooperative societies, and there exist 1,650 weavers' cooperative societies in the State of Tamil Nadu. Yarn was supplied, subsidy was given and every month the cloth was sold becuase rebate was given. Of course, when we were in in power in 1976, 90 days' rebate was given. Subsequently it was reduced to 60 days and 30 days. (*Time bell rings*) .. Sir, kindly give some more time--four, five minutes.

Again the weavers were terribly affected. When we came back to power again, at the beginning of 1989 the rebate was increased again. Ninety days' rebate was given an later it was increased to 100 days' rebate. Nowhere else in the country but only in the State of Tamil Nadu was 100 days' rebate given and, therefore, they could get yarn.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : It was allowed in Madras. Let them also adopt it....(*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY : You have to make a deep study of what steps we had taken in Tamil Nadu to solve the problems of the weavers.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam) In Assam, everywhere ...(*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY : When your time comes, you tell about Assam. This is very important because the whol country is facing this problem. Please let me complete.

Then, by conducting exhibitions and giving encouragement to the handloom

[Shri V. Gopalsamy]

weavers to sell their cloth, Coptex earned a profit of Rs. 3 crores during our regime. A subsidy of Rs. 42 crores was given to the weavers because we gave 100 days' rebate. We also implmented a housing scheme. Pucca, concrete houses were constructed, and in one concrete house they could operate two handlooms. Reservation of cloth of particular categories was made, and it had been accepted by the Central Government and many State Governments. This reservation policy should be strictly implemented. So, cloth was categorized and there was reservation of cloth for handloom weavers. We had an insurance scheme also and we gave Rs. 10,000 if a weaver died. So, the insurance scheme should also be expanded. Modernization of handlooms to the tune of Rs. 31 crores as estimated. New Design Centres should be encouraged. Then only they can compete with the power loom industry. Therefore, during those two and a half years there was no agitation in Tamil Nadu. Thoug there were three million handloom weavers in Tamil Nadu, there was no agitation there during our time. But now, some problems have cropped up again. Some days back, 3,000 handloom weavers courted arrest in Kancheepuram and some were arrested in Madurai also.

Mr. Gehlot has taken keen interest in the matter--he is a dedicated man. Therefore, I would like to inform the Government that the steps taken by the Tamil Nadu Government in the handloom sector during our tenure--during the tenure of the DMK Government--to solve the problems of the handloom weavers would guide them. Therefore, I would like to insist upon the Government of India giving protection to handlooms by reserving certain varieties of cloth for their exclusive production in the handloom sector. Again, there should be design support and provision of technological inputs through a number of weaver service societies in our country, which has been admitted by the Minister in reply. to a question. That should be immediately implemented. Then only can you erase the tears of the weavers. Otherwise, you cannot stop the starvation deaths.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य कोटैय्या साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को उठाया है और हैंडलूम उद्योग के बारे में और जो भूख से मर रहे हैं उनके बारे में यह बहुत ही जरूरी प्रश्न था जिसको उन्होंने यहां उठाया है । यह भी अच्छी बात है कि उन्होंने काफी तफसील में बहुत सी बातों को रखा । मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरा अनुभव आंध्र का यह है कि तीन साल पहले भी मैं वहां गया था जब 9 आदमी मर गए थे जो हैंडलूम के वर्कर थे और तीन किसान मर गए थे जो रुई की खेती करते उस राज्य में । इसलिए मैं जो भी वहां हंगर डैथ हुई है उसके लिए भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो नीति है उसको इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार मानता हूं । जो केन्द्रीय बजट आया उसके बाद जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है धागे की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है । पहला कारण इन अभागे लोगों के मरने का यह है कि आपके बजट का यह नतीजा है । दूसरा कारण यह है कि खुद वहां की सरकार ने हैंडलूम कपड़ा खरीदना बंद कर दिया और हैंडलूम न खरीदकर पावरलूम का कपड़ा अपने राज्य सरकार के इस्तेमाल के लिए, वर्दी वगैरह के लिए खरीदा गया । तीसरा अभाग्यपूर्ण काम यह हुआ कि सरकार ने इजाजत दे दी 13 लाख बेल्स काटन का ऐक्सपोर्ट करने की जिसके चलते उसके दाम बढ़ गए । इसी तरह धागे का भी निर्यात हुआ जिसके चलते उसके दाम और बढ़ गए ।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि किस तरह से धागे का दाम तेजी से बढ़ा है । मैं केन्द्रीय सरकार के मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आबिद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अनुशंसाओं को सरकार ने क्यों लागू नहीं किया है । इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार आबिद हुसैन साहब की कद्र करती है लेकिन उनकी रिपोर्ट को इन उद्योगों के लिए उन्होंने नहीं माना और इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लोग आज भूखे मर रहे हैं । यह तमाम लोगों के लिए लज्जा की बात है ।

श्रीमन्, इकानामिक टाइम्स कोई राजनीतिक अखबार नहीं है, मैं उसके

संपादकीय दिनांक 2 नवंबर का एक वाक्य आपको पढ़कर सुनाता हूं–

> "The State Government has brushed aside these deaths as resulting largely from ill health and oldage. This approach betrays a complete indifference and apathy to the manifold problems of handloom weavers."

इसमें सरकार को सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है। ये गरीब लोग कब मर रहे हैं? ये तब मर रहे हैं जब कि उद्योगपतियों का मुनाफा इस देश में कई गुना तेजी से बढ़ गया है। मैं आपको फिर इकानामिक टाइम्स का ही जो संपादकीय है उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं –

> "The consolidated financial results of 650 listed companies for the first half of 1991-92, published in this paper on Monday, show that the corporate sector has fared much better than expected. Sales have risen by 22 per cent, operating profits by 32 per cent, gross profits by 34 per cent and net profits by 25 per cent.

Again,

> "Most companies hvae been able to beat inflation by passing on more than their higher cost to consumers".

यह आपकी सरकार की नीति है। लोग मर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इलाज क्या होगा। इलाज हमको नहीं लगता कि कुछ होगा। अभी माननीय सदस्य गोपालजी ने कहा कि बुनकरों ने कहा कि हमें विष लाकर दे दीजिए मरने के लिए। हम लोग कहते हैं कि विष खाकर क्यों मरते हो। मरना ही है तो ए.के.–47 राइफल उठा लो, फिर तुमको सरकार खोजेगी, विष खाकर मरने की बात क्यों करते हो? यही इस देश की स्थिति हो रही है। इसीलिए हमारे देश में जब गरीबों को मारा जा रहा है उस समय जब कि पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? तब दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। इसीलिए अत्यन्त ही लज्जाजनक स्थिति में इस सरकार ने सारे देश को पहुंचा दिया है। आप एक्सपोर्ट बाजार की बात करते हैं लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इसी कमेटी की रिपोर्ट से कि अपने देश के समाज का एक बड़ा हिस्सा अत्यन्त दरिद्र होता जा रहा है। वह कपड़ा नहीं खरीदता। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में इस देश की आबादी का 2.95 परसेंट आदमी कपड़ा नहीं खरीदता था। 1988 में इस देश की आबादी का 3.95 परसेंट आदमी कोई कपड़ा नहीं खरीदता। ये गरीब लोग कहीं से पुराना कपड़ा मांग कर या इधर-उधर से लेकर पहन रहे हैं। यह स्थिति हो रही है। आप बाजार को दुनिया में खोजे चलते हैं। जिनको आप नंगा करते हैं, जो अपनी मां-बहनों को नंगा होते नहीं देख सकते वे अगर हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। क्या हमारे और आपके भाषण से उनका पेट भरेगा? क्या इससे उनकी लज्जा का निवारण होगा? मैं जानता हूं मंत्री महोदय दूसरे ख्याल में हैं और उनके ख्याल से कुछ नहीं होना है। जिस रथ पर वह बैठे हुए हैं वह रथ सारे भारत को नंगा नाच कराने के लिए ये जा रहा है। हम कर ही क्या सकते हैं। मैं उनकी हमदर्दी को जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनकरों को भुखमरी से बचाना असंभव काम नहीं है।

मेरा कहना है कि इसे नाइन्थ शेड्यूल में ले जाना था तो 500–600 वर्ष से क्यों सोए हुए थे, क्यों नहीं ले गये? जो एक्साइज ड्यूटी को आपरेटिव्स को माफ करनी थी वह क्यों नहीं की? आप आज जो कह रहे हैं वह पहले किया क्यों नहीं। उनके कल्याण के लिए जिन योजनाओं को आबिद हुसैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, जैसे थ्रिफ्ट फंड को प्रोविडेंट फंड स्कीम की तरह चलाने की बात थी उसको आपने क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो इसका नतीजा तो यह होना ही था जो आज हो रहा है। अगर आप सभी को भारी संख्या में इस इंश्योरेंस स्कीम में नहीं लाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो वे बेचारे मर जाते हैं। गरीब हैं उनकी कोई नहीं सुनता है। इसलिए

[श्री चतुरानन मिश्र]

से जो मरते हैं उसका कोई तो असर होगा। किसी न किसी दिन उसका असर होना ही है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने देश में रूई पैदा होती है। रूई के दाम भी फ्लकचुएट करते हैं । रुई के दाम में, कपड़े के दाम में, सूत के दाम में मेल नहीं रहता। मैं सुनाता हूं कैसे । 1984 के अंदर रॉ कॉटन का मल्य अगर 235 था तो 1989 में 297 हो गया यानि 62 प्वाइंट लेकिन यार्न का 144 प्वाइंट बढ़ गया । नाइलोन से हम कम्पेयर करें तो इसका भी दाम बढ़ना चाहिए जब दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो : नाइलोन का भाव 12 प्वाइंट बढ़ा । इसका मतलब सीधे-सीधे यह है कि लोग ब्लैक करते हैं, सीधे-सीधे आपकी नीतियां उनको मदद करती हैं । सरकारी आंकड़ों का यह हाल है कि हैंडलूम क्लाथ के क्या दाम घटते बढ़ते हैं यह सरकार नहीं रखती है। उसमें पावरलम को मिला देती है ताकि सही बात लोगों के सामने न जा सके। वैसे भी सरकार असहाय है । मैं आपको कॉटन प्रोडेक्शन डाटा देता हूं । जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देती है और जो कॉटन एडवाइजरी बोर्ड देता है इन दोनों [प्राइस में 15 से 20 परसेंट का फर्क लगातार रहता है। एक ही सरकार का एक मुंह कुछ कहता है और दूसरा मुंह कुछ कहता है । वैसे भी दो मुंही सरकार तो है ही । अभी कहेंगे कि हमने रिलीफ बांट दी है क्योंकि वे मर रहे थे । मंत्री जी ने अभी यह पढ़कर सुनाया । लेकिन कोई कहे कि उनके मरने के बाद यह अकल आई, उनके जिंदा रहते यह अकल क्यों नहीं आई? यह सीधा सवाल उठकर खड़ा होता है।

मैं तफसील में नहीं जाना चाहता । कुछ सवालों को रखता हूं । क्या कारण है कि आबिद हुसैन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी इस मामले में, सरकार ने उसको अभी तक क्यों नहीं लागू किया ? क्या कारण है जब ये लोग भूखे मर रहे थे तब वहां की राज्य सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया । क्योंकि अभी आप बजट पूर्व दर पर धागा देने की बात करते हैं तो इनके मरने के पहले क्यों नहीं किया । यह आपकी स्टेटमेंट में है कि पूर्व बजट दर पर धागा देंगे न तो इसको आपने किया और न आपने इस बात की कोशिश की कि मिलों को बांध दें कोआपरेटिव सोसाइटीज के साथ ताकि निश्चित दर पर धागा नियमित मिले । तीसरा प्रश्न यह है कि जो लोग भूखों मरे हैं वे कोआपरेटिव के सदस्य हैं या सदस्य नहीं हैं ? अगर गैर सदस्य लोग मरे हैं तो सरकार उनके बारे में क्या करने जा रही है ? क्योंकि सभी कोआपरेटिव के सदस्य हो ही जाएंगे, यह सरकार के हाथ में नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना ही सरकार का नियंत्रण कोआपरेटिव पर रहेगा उतनी ही असहाय कोआपरेटिव सोसायटी होगी । इसलिए मैं सरकार से यह भी प्रश्न पूछता हूं कि असली स्थिति क्या है ? मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि जो आप राहत देते हैं वह वीवर को देख करके दीजिये । यह नहीं होना चाहिए कि किसी संस्था को दीजिये । हो सकता है कि कुछ कोआपरेटिव सोसायटीज अच्छा काम कर रही हों। लेकिन मेरा अनुभव है कि बहुत-सी जगहों पर कोआपरेटिव सोसायटीज मिडिलमैन की तरह भ्रष्टाचार में विलप्त हैं और मिडिलमैन की तरह से मनाफाखोरी में पैसा खा जाती हैं । गरीबों के पास पैसा नहीं पहुंचने देती हैं । इसलिए सरकार नीति में कोई परिवर्तन करने की क्यों कोशिश नहीं कर रही है ?

मेरा अगला प्रश्न यह है कि रूई और यार्न के दाम आज जिस तरह से अनियंत्रित ढंग से बढ़ते जाते हैं उन्हें आप कैसे नियंत्रित करने जा रहे हैं क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि मार्केट रूल ओपरेट करेगा ? मार्केट रूल में तो 73 आदमी मर गये हैं और कुछ मरने वाले हैं । मार्केट रूल के मुताबिक तो यही होगा । इसलिये हम कम्युनिस्टों के बारे में आपको जो नापसन्दगी हो, जितनी आलोचना करना चाहते हों, वह कर दीजिये, लेकिन आज भारत का यह नागरिक मर रहा है । इसलिए इन बिन्दुओं पर आप हमको बतायें कि आप इस तरह की नीति में कोई परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं ? यही मुझे आपसे कहना था, धन्यवाद ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing a serious problem being faced by the handloom

weaver of Andhra Pradesh in particular. It is very unfornunate, that even after 44 years of independence we could not protect the interests of the handloom weavers. It was a national commitment and it was repeatdly pledged by our national leaders during the course of the struggle for independence that the interests of the handloom industries would be protected. What has happened? They have bcome more down-troden and more starvation deaths are taking place. It is very unfortunate that the Government have followed wrong policies which could not protect the interests of the handloom weavers.

My friend, Mr. Pragada Kotaiah has already explained how their interests were suffering because of the discriminatory policies being pursued by the Government. The Government has not seen to it that the yarn is sold to the handloom weavers at a higher rate than to the mills and to the looms. More yarn was exported and less yarn was supplied to the weaving sections. Apart from this, high cost of chemicals and colours added to their difficulties, that is why in purchasing they were suffering and in marketing their products also they were suffering. In both ways they were suffering a lot because of the market discrimination. The were allowing exports from the textile mills but less exports from the handloom sector. All these thins go to show that the Government is very callous towards protecting the interests of the handlooms weavers. It is exactly because of this policy more starvation deaths have taken place in Andhra Pradesh. It is reported in the newspapers that 73 persons have died due to starvation.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : More than 100.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO : That is what I am going to say. Now it is more than 100.

On the 20th November, itself I made a special mention about the plight of the handloom weavers in Andhra Pradesh. Then, I produced a list of 91 persons who died along with the details. I have got all the newspaper cuttings as well as the list of 91 persons who have died. Added to that in the recent period 4.00 p. m. so many more have died. So, it comes to about 100 deaths. Some time back, in Parkasam District, there were deaths of cotton-growers. Many committed suicide because remunerative prices were not given. And now, for want of yarn, our handloom weavers are suffering. And now these people are resorting to even suicides. Some cases of suicide are there. The overwhelming problem is that they are thrown to that misery. I had a survey made in Mangalagiri of 100 families. At my instance, some friends made that survey in that village. That survey showed that out of them, 90 families were suffering from anaemia;90 families altogether, elders and youngsters, were suffering from anaemia. If such is their fate, any disease can attack them very easily. After having starved for so long, if they take aything, even a particle of food, then naturally diarrhoea infection or some other infection would be there and they would die because of that. Our Andhra Pradesh Government had determined to deny that any starvation death had taken place in Andhra Pradesh at all. It is very unfortunate. They tried to bluff all the while. Now I am glad that at least our hon. Minister gives another story. "It is not the occasion to go into the question as to whether these deaths are starvation deaths or not. It is a matter of paramount concern that a large number of deaths have taken place". That is what he says. So, a large number of deaths have taken place. Because of their anaemic conditions all these things followed. The Andhra Pradesh Government had been totally neglecting those starvation deaths. They wanted to ingnore that. They were bluffing. And now they come forward with a list of persons who died. Why should there be a list ? It is not a question of registering births and deaths here. So, in this period, due to the suffering that has prevailed upon the handloom section they were dying. If this is the truth, now, you say that Rs. 5000/- is given towards ex gratia payment to beraved families. What is Rs. 5000/- ? The responsibility of the Governments was there all along and because of the policies pursued by the Central and the State Governments, people were starved to death and this responsibility must be borne by the Government itself. We have been seeing on so many occasions that Rs. 25,000/-, Rs. 50,000/- and Rs. 1 lakh are paid as ex gratia payments to those people who suffered and who died, who were shot dead, who were killed, who starved to death, etc. Why the poor handloom weavers, the bereaved families, should be paid only Rs. 5000/-? I think the hon. Minister would attend to it. This amount is not enough. And that too, straightway the Government is not paying. Through some other agency they would like to distribute the money because they do not want to accept that they were starvation deaths and it was their responsibility to see that the bereaved families are helped. All these things cannot be bluffed away like that and they should immediately see to it that proper attention is given. In our country, it is beleived that the Governments elected should see that nobody dies out of hunger. In order to

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

keep up to that, they go on bluffing that no starvation deaths were there. It is happening even in Tripura. Five hundred people died according to press reports but the Chief Minister goes on denying that. So urgent relief measures are required to be taken. A sum of Rs. 1,000 is being given per handloom weaver at the interest rate of 11½ per cent as loan. A man who cannot repay this amount is asked to pay interest also. It is very undesirable and they should see to it that Rs. 1000 loan is given to all the suffering families without interest and it should be liberally attended to.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : Please conclude.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO : I am concluding, Sir. The 22 items that are reserved for the handloom sector, how are they going to be implemented ? We were told that in this Parliament Session a legislation would be brought to see that these 22 items are implemented. These items have already been passed by Parliament but a case is pending before the court and unless these items are included in the Ninth Schedule. it would not be possible to implement it. So the Government should see to it that these are included in the Ninth Schedule. The Government should also see to it that these 22 items are strictly reserved for the handloom industry.

As regards consumption allowance, when such is the plight of the handloom weavers, how has it been proposed in our Budget that the consumption allowance which was given for their export earlier, would be taken away ? How could the Government propose such a thing at all ? They are quite indifferent to the handloom industry. They are not caring whether the people are living or dying. This type of indifference cannot be tolerated. I hope the Government would look into the matter seriously and offer large scale aid to the handloom industry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Sir, the plight of the handloom weavers in Andhra is in sharp focus in today's discussion. But, Sir, the largest number of weavers are actually in the State of Tamil Nadu where the situation is as bad—perhaps not at the level of starvation—but in fact, their situation is also totally on a borderline. You have the same kind of problem faced by the powerloom weavers in a place like Bhiwandi where they not only have to suffer these high prices but they also have to suffer communal discriminations and disruptions. In fact, what is required is a national policy from the Government on this not only for the plight of the weavers in Andhra—the extreme situation there has brought this matter to focus—but I think what is required is an attention on a war-footing as far as weavers of India are concerned.

Sir, the anomaly of the situation is brought out by the fact that the cloth produced by such weavers is normally preferred by the masses of India and it is a labour intensive technology, which means it generates a lot of employment in terms of per unit capital. Yet our economic system today is so worked and lopsided that it is more profitable to produce cloth for a hundred million people than for the remaining 750 million people. For a country where the market is as large as 750 million people, the producers for them find that they are in economic difficulties and that producing such a cloth is unprofitable, whereas those who produce cloth for the top hundred million people, they are making a fairly high level of profit.

This shows a gross lopsidedness in our economic system and also the havoc that the black-money system plays with our economy. Unless you correct that malaise, this lopsidedness in our economic system, this warped aspect of our economy, the weavers are not going to be in a position to be able to really get the benefits of the large market that India is. Therefore, I would say that rather than thinking in terms of providing certain reliefs as mentioned in the statement made by the Minister her , what we should really think is how to make these weavers as part of the vibrant, growing economic system. And I would certainly say that since there is a tremendous market for handloom abroad, we should, in fact, take special steps to see tha we provide marketing facilities, in rastructural facilities, for these weavers to be able to export their goods abroad and thereby they would be able to earn a much higher rate of return on their investment. The point I wanted to make was this. While we may take immediate steps in terms of relief-and I hope this is true—, the immediate provocation for the prsent State, of course, is budget whereas in an unthinking way the prices of yarn have gone up and on the other hand, the mills are not paying their dues to the weavers in time and there is no machinery to police them. That is the immediate provocation but I think in the long-term we have to have a national policy in which handloom become a profitable activity, particularly so far as that market is concerned.

Sir, Mahatma Gandhi had popularised khadi to such a great extent and indeed the Congress Party of the freedom movement had made this into a kind of national fashion. Today, of course, wearing

Indian things, Indian dresses, are now going out of fashion. In fact, a large number of Ministers who go abroad go in suit and boot, in western three-piece suits and tie coats, and perhaps some of them take, umbrellas···(*Interruptions*)··· Yes, waist-coasts too and even a cigar on the side pocket. If the Ministers of the country representing India··· (*interruptions*)... It is all right for communists to wear westrn dress because that is part of their culture. I think a party which swears by Mahatma Gandhi should ensure that its Ministers when they go abroad wear Indian products and Indian dresses so that that can get popularised and even in the country they should do the same···(*interruptions*)··· I am talking not in terms of criticism. I am saying that there is a certain cultural change which has come, but hich is not what Mahatama Gandhi had envisaged. And unless we make this into a fashion, these poor people will not be able to get the demand and market that they need and that is what is at the core. This is the point of order I wanted to make.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी।

महोदय, सबसे पहले तो मैं श्री प्रागदा कोटैया जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक बहुत ही सामयिक विषय की तरफ सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। श्रीमन, विषय केवल गम्भीर ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वह देश जिसे कृषि प्रधान देश की संज्ञा दी जाती हो वह मूल्क जो अपने आपको खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने का दम भरता हो, उस देश में लोग भूख से बिलखकर मर जाएं इससे बड़ी शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। मरते तो यहां सैंकड़ों लोग रोज है, कभी रेल दुर्घटना में, कभी सड़क दुर्घटना में कभी विमान दुर्घटना में, कभी आतंकवादियों के हाथों से, कभी प्राकृतिक आपदा के कारण। लेकिन इन तमाम हादसों में सरकार की सीधी सीधी जिम्मेदारी कई बार स्थापित नहीं की जा सकती। लेकिन जब लोग और अन्न के मर जाएं, जब लोग बगैर खाने के मर जाएं, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती है और शायद यही कारण है कि सरकार के प्रतिनिधि यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि यह लोग भूख से मरे हैं। सरकार के प्रतिनिधि यह दलीलें पेश करते हैं कि यह लोग भूख से नहीं मर सकते थे, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले राशन की दुकान से अपना राशन खरीदा था।

वह यह दलीलें पेश करते हैं कि इन मरने वालों के पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में इनके पेट से चावल के दाने पाये गये हैं, इसलिए इन्हें भूख की मौत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन, महोदय, मैं बधाई देती हूं उन खोजी पत्रकारों को जिन्होंने शासकों और प्रशासकों की यह बेतुकी दलीलें मानने की बजाए सत्य को उजागर करने की कोशिश की।

अंग्रेजी पत्रिका, फ्रंटलाईन की पत्रकार टीम आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गई। वहां एक राधाकृष्ण मूर्ति नाम के बुनकर की मौत हो गई थी। वह उसके घर गई और जब उसने वहां के प्रशासकों से बात की तो वहां के उप-जिलाधीश ने उन्हें कहा, राशन कार्ड दिखा करके कहा कि देखिये आप कह रहे हैं कि यह स्टार्वेशन डेथ्स हैं, यह भूख से मौतें हुई हैं, पर यह भूख से हुई मौतें नहीं हैं। इसी राधाकृष्ण मूर्ति ने आज से नौ दिन पहले अपनी राशन की दुकान से बीस किलो चावल खरीदा था, इसलिए वह भूख से कैसे मर सकता था।

लेकिन वह खोजी पत्रकार इस तरह से बाज नहीं आये, वह आगे गये, आगे जाकर उन्होंने सत्य बात का पता लगाया और आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वह इस सच्चाई को खोज कर लाए और उन्होंने अपनी पत्रिका में छापा कि उस राधाकृष्ण मूर्ति के राशन कार्ड से बीस किलो चावल खरीदा जरूर गया था, मगर वह चावल उसके और उसके परिवार वालों के लिए नहीं खरीदा गया था, महोदय, बल्कि बीस किलो चावल खरीदने का पैसा न होने के कारण उस राधाकृष्ण मूर्ति ने अपना वह राशन कार्ड अपने पड़ौसी को मात्र दस रुपये में बेच दिया था, ताकि वह उस दस रुपये से कम से कम उस दिन तो पेट भर सके। यह सच्चाई थी।

शर्म आनी चाहिए हमारे शासकों प्रशासकों को, संकोच होना चाहिए उन्हें, कम से कम मृतकों के साथ इस तरह का उपहास करते हुए। लेकिन नहीं, अपनी साख को बचाने के चक्कर में इस तरह की शर्मनाक दलीलें देने में भी हमारे लोग बाज नहीं आते।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

महोदय, जो मौतें हुई हैं, वह कोई दो-चार या पांच-दस की संख्या में नहीं हुई है। यह जो सूची प्रकाशित की है फर्टलाईन ने, अकेली इस पत्रिका की सूची के अंदर तीस लोग तो गुंटूर जिले के शामिल हैं। और बाईस लोग प्रकाशम जिले के शामिल हैं। 52 लोगों का नाम तो इस सूची में लिखा है, जैसा कि मुझे पहले पूर्ववक्ता कह रहे थे और जिसके साक्षी बने थे कोटैया जी कि लगभग सौ लोग अब तक मारे जा चुके हैं और यह सूची जो प्रकाशित हुई है, इसमें अगर आप लिखी हुई उम्र देखें, तो दिल दहल जाएगा। इस सूची में बीस साल का एक देवनागपुरी निवासी साथी बाबू भी शामिल है और एक 69 साल का बूढ़ा इलावर्म का राम कोटैया भी शामिल है। यह लोग कौन हैं ? यह लोग वह हैं जिनकी कला पर गर्व करते हम अघाते नहीं हैं। यह वह लोग हैं, जिनकी मेहनत से जिनकी कल्पनाशीलता से, जिनकी अंगुलियों से बुने हुए वस्त्र पहन कर किसी भी मानव देह को बख्शा जाता है। यह वह लोग हैं जिनका कपड़ा बेचते समय बड़े-बड़े होर्डिंग लगा करके, विज्ञापनों में लिखा जाता है :—

"Your dream has come true; ear handlooms."

यह वह लोग हैं जिनके बने हुए वस्त्र "अपना उत्सव" जैसे आयोजनों के अंदर सरकार सगर्व प्रदर्शित करती हैं और यह वह लोग हैं, जिनके बुने हुए वस्त्र पहन कर हम राजनेता लोग स्वदेशी का ढोल पीटते हैं। लेकिन हमें भव्यता बख्शने के बाद यह लोग स्वयं किन हालातों में रहते हैं, यह देखने की शायद हम में से किसी को फिक्र नहीं है।

यह तो मौतों का हादसा हो गया, तो यह मामला सदन में भी उठ गया, वरना अगर आप इनके सामान्य जन-जीवन को देखें, तो यह एक आम नागरिक की जिंदगी भी नहीं जी रहे हैं। क्यों नहीं जी रहे हैं, क्योंकि यह तीन तरह का शिकार होते हैं — एक तरह मास्टर वीवर के शोषण का शिकार होते हैं, दूसरी तरफ पावरलूम, जो कारखानों में बने हुए कपड़े हैं, उसकी प्रतियोगिता के शिकार होते हैं।

और तीसरी तरफ हमारी सरकार की नीतियां बनाती है, तो उस समय इनकी तरफ देखा तक नहीं जाता। मास्टर वीवर जिनका नाम है मास्टर वीवर, वह बुनाई के अलावा सब कुछ करते हैं और वह मास्टर वीवर इन्हीं लोगों के हाथों की बुनी हुई साड़ियों को चार और पांच हजार रुपये में बेचते हैं। यह साड़ियां सरकारी इम्पोरियम में बिकती है, लेकिन इन्हीं लोगों को उसी बुनाई का चार सौ रुपया भी नहीं दिया जाता है।

कारखानों की हालत यह है कि कारखानों और मिल में बना हुआ कपड़ा ज्यादा सस्ता होता है।

आसानी से धलने वाला होता है, लंबी देर तक चलने वाला होता है। इसलिए मध्यम वर्ग में अब उस कपड़े का ज्यादा आर्कषण होने लगा है। जहां तक सरकार की उपेक्षा का सवाल है, सरकार की उपेक्षा का आलम तो यह है कि महोदय, कोटैया साहब, जिन्होंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, उनके एक खत के जवाब में, आज के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि वह हथकरघा से बने हुए कपड़ों पर भी एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शल्क लगाने की सोच रहे हैं। खत में उन्होंने लिखा क्या था ? खत में उन्होंने यह लिखा था कि पावरलूम सैक्टर और मिलों में बनने वाले कपड़े वाले लोग 910 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं उस पर निगरानी करिए बजाय उसका जवाब यह आता है कि हां, हम निगरानी करेंगे, जवाब यह आया कि हां, हम हडलूम के बने हुए कपड़े पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात सोच रहे हैं। हमारे एक कहावत है, नमाज बख्शाने गए थे, रोजे पल्ले पड़ गए। वह हालात इनकी हुई होगी जब इन्होंने इस खत का जवाब लिखा होगा। सरकार की नीति हालत यह है महोदय, कि स्वयं सरकार ने यह कहा है कि 50 फीसदी धागा जो बनेगा वह हैंक यानं बनेगा जो कि इन बुनकरों को दिया जाएगा, लेकिन कोई सरकारी मशीनरी इस बात की निगरानी नहीं करती कि वह धागा 50 फीसदी बनता है या नहीं

और बनता है तो उसका कितना हिस्सा एक्सपोर्ट होता है और कितना इन बुनकरों को दिया जाता है । अब जो बजट आया है, उस बजट प्रावधानों के बाद तो आलम यह है कि धागे का दर इतना ऊंचा हो गया, दाम इतना ऊंचा हो गया कि धागा खरीद ही नहीं सकते । पहले तो धागा कम होने के कारण से वह कभी-कभी रोजगार की इंतजार में बैठा करते थे, अब तो धागा न मिलने के कारण जिन खड्डियों पर वह कपड़ा बुना करते थे, श्रीमान्, आज उन्हीं खड्डियों से लटक करके अपनी जान दे रहे हैं । वह खड्डी जो उनकी आजीविका का साधन बनती थी, वह खड्डी जो उनको रोटी मुहैया करवाती थी, वह खड्डी, आज जब वह जीवन के संघर्ष में हार रहे हैं तो उनको मौत की नींद सुला रही है । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ सरकार बेफिक्री की नींद सो रही है महोदय, पहली मौत भूख के कारण इन बुनकरों की अगस्त की 30 तारीख को हुई थी और तब से लेकर आज तक यह सिलसिला जारी है । आज यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया तो मंत्री महोदय इस सदन में वक्तव्य लेकर भी आ गए वरना कोई ठोस कदम इस समस्या की ओर सरकार ने उठाया नहीं है और आज भी कौनसा ठोस कदम उठाया है । यह मंत्री महोदय का वक्तव्य है, यह क्या किसी ठोस प्रयास की तरफ इशारा करता है या केवल रस्मी है ? उन्होंने अपने इस वक्तव्य के अन्दर क्या कहा है ? बड़ी शान से सर ऊंचा करके मंत्री महोदय यहां कह रहे हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक बुनकर के परिवार को सहायता के रूप में, स्थानीय संस्थाओं के माध्य से 5000 रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है । इंसानी जान की कीमत मात्र पांच हजार रुपये और जो केवल यह सरकार आंक सकती है । पांच हजार रुपये मरे बुनकर के प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता मात्र पाच हजार रुपये और ठीक है शायद, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि हम सरकार में आयेंगे तो कीमतें कम कर देंगे । बाकी चीजों की कीमत तो यह कम कर नहीं सकते, इंसानी जान की कीमत आंकना इनके अपने हाथ में है, तो कम करके आंक दी है पांच हजार रुपये । मैं कहना चाहती हूं कि सरकारें भी आदमी की हैसियत को देख करके उसका मुआवजा देंगी । एक बुनकर की हैसियत को देख करके इन्होंने पांच हजार रुपये का मुआवजा तय किया और वह भी सरकार नहीं देगी बल्कि सरकार वहां की स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से दिलवायेगी । और क्या कहा है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि बुनकरों के बकाया भुगतान की आवश्यक धनराशि राज्य सरकार तुरंत जारी कर देगी । सहमत हो गए हैं, बड़ा एहसान किया है, मुख्य मंत्री ने सहमत हो कर । यह तो उनका अपना बकाया है, उनका अपना पैसा है जो कपड़ा वह बन कर दे चुके हैं उसके बदले में जो राज्य सरकार ने पैसा देना है यह तो वह बकाया है । महोदय, मैं पूछना चाहती हूं राज्य सरकार को बकाया रखने का अधिकार किसने दिया ? एक ओर गरीब का बकाया रखते हो, यह कोई साधन सम्पन्न लोग हैं, कोई धनाड्य लोग हैं जो कि सरकार को उधारी दे सकते हैं और जो इस बात को सह सकते हैं कि सरकार उनका बकाया रख ले ? यह तो वह दिहाड़ीदार मजदूर हैं, महोदय, जो नित कुआं खोदते हैं और नित पानी पीते हैं । अगर इनका बकाया भी सरकार रख लेगी तो यह कैसे खायेंगे ? मेरा आरोप है कि सरकार ने बकाया रख करके इन बुनकरों को मौत की ओर धकेला है और अभी भी यह कह रहे हैं कि हमको लगता है कि हमें उम्मीद है कि बुनकरों की बकाया की समस्या में वांछित सुधार होगा । वांछित सुधार यानी उस समस्या का निराकरण नहीं होगा । इसके मायने है कि आज भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार उनका पूरा बकाया देने को तैयार नहीं है केवल उस समस्या में वांछित सुधार करना चाहती है, यानी थोड़ा-बहुत देकर सदन की तसल्ली करवा देना चाहती है ।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

महोदय, मंत्री महोदय एक विस्तृत कार्य योजना लेकर आए हैं । इस विस्तृत कार्य योजना का उद्देश्य और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि सदन का ध्यान इस समस्या से भटक जाए । केवल एक मात्र उद्देश्य लिए हुए हैं यह विस्तृत कार्य योजना । चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं आखिरी तौर पर मंत्री महोदय से केवल यह कहना चाहती हूं कि यह विस्तृत कार्य योजना के लिए समय बहुत पड़ा है, मंत्री जी, दीर्घकालिक योजनाएं तो बनती रहेंगी । यह तो आपकी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा है, जब तक आपका मंत्रालय चलेगा, सरकार चलेगी, योजनाएं बनती रहेंगी लेकिन इस समय आप समस्या का तात्कालिक समाधान कीजिए । लोग मर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए सवाल इस बात का है ? इसलिए तात्कालिक समस्या के तौर पर क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार उनका पूरा-का-पूरा बकाया भुगतान कर दें ? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि 5 हजार के बजाय समुचित मुआवजा उन मरनेवालों के परिवारों को दे दिया जाए ? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि यह हैंडलूम वीवर्स जिस तरह से मर रहे हैं जिनको आप प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण किसको देंगे आप ? अगर उनको आप रोटी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) पीठासीन हुए]

आपकी । अगर उनको रोटी मिल जाएगी तो उनके बच्चे अपने आप प्रशिक्षण ले लेंगे ।

श्री हेच० हनुमनथप्पा (कर्णाटक) : सुषमा जी, आपकी सरकार ने मरनेवालों की कितनी कीमत लगायी ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : पांच हजार रुपए तो नहीं लगायी... (*व्यवधान*)... अगर आप 5 हजार से संतुष्ट हैं तो मझे कुछ नहीं कहना है । ... (*व्यवधान*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA : It is not much ? ...(*Interruptions*)...

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: (Andhra Pradesh) : You are all callous people. You have not been able to feed the weavers. This is the condition now... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Hanumanthappa, the whole House is concerned and I know you are also concerned. But let us understand the feelings of the Members. (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am also serious, I am also concerned.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, मैं तो आपके माध्यम से केवल यह कहना चाहती हूं कि अगर इनको रोटी मिलेगी तो इनके बच्चे अपने आप प्रशिक्षित हो जाएंगे । मगर अगर ये रोटी के अभाव में मरेंगे तो प्रशिक्षण लेने कौन आएगा ? कौनसा इंसेंटिव होगा बाकी लोगों को प्रशिक्षण देने का अगर इनको रोटी नहीं मिलेगी ? इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या समस्या के तात्कालिक समाधान के तौर पर आप उनको पूरा मआवजा दिलवाएंगे? इसके साथ-साथ क्या आप उनके घरों में राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे ताकि आगे होनेवाली मौतों को रोका जा सके ? मुझे इतना ही कहना था । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Now, Prof. Saurin Bhattacharya.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, as I was going through the statement made by the honourable Minister of Textiles, the only part which seemed to be a bit of a relief in a very grim situation like this was that in which he says, "Let us not debate whether it is a starvation death or not." I remember, Sir-perhaps the Minister may not because he is of a much younger age-in our younger days, when Bengal faced a great famine in 1943, the then Secretary of State for India, Rt. Hon. Amery, declared that the Bengali people were dying of overseating ? I mean to say that something like that has crept in. In this discretion he has said that such controversies should be avoided. That is a very sensible thing, no doubt. But there is the other part also. I would have been happier in there was some analysis of the reasons leading to this situation, the tragic deaths of weavers, and I would have been happier if the Ministr had not mentioned the figure of five thousand rupees for the families of the

dead weavers. I was just trying to find out whether it was for all the weavers taken collectively or for each individual weaver who has died. The statement does not make it clear. Naturally, I take it that it is for each person dead. This is a very pitiable sum, indeed,Earlier also, I reiterated here that in my students days, we read a poem called 'the Song of Shirts' There was a line in it: "Oh God, blood so cheap and bread so dear." It reminds me of those lines, long after that poem was written. If it is Rs. 5,000, it was better not to have been mentioned here at all. The question is that some statistics have been given here. I am very weak in arithemetic. They say, crores of ruppes on this account and that account, janata cloth and other things, and what the State Chief Minister has given, what the others have given, and what the subsidy has been , etc. But the basic point, in a casual manner, was raised by Dr. Subramanian Swamy that in our country, there should be State-run labour intensive industries whereas we are cutting down the imports, but increasing the imports of foreign technology and foreign investments. That being the industrial policy of the Government of India, they seem to be proud of it. They seem to be proud to beg at every door. Our country is known to be a country of beggars. But never before was it so as it is during the present regime. And by such imports of a few crores of rupees of inputs, we do not know how they will be utilised or whether they will be able to solve the problem of the weavers whose tragic tale was told by Mr. Kotaiah, who hails from a weaver's family, both from the mother's side and the father's side. here is no realisation of that aspect. That is really the underlying issue which should be taken care of. I do not like to unnecessarily bring the Minister. But it is a question of approach. Only day before yesterday, I received a reply to my question here. It says, the registered unemployed are 358 lakhs. There is no system of maintaining the statistics of those who were unable to register themselves. And that h s been given as agricultural labourers. Their number would be about 11 crores. And their daily income on an average is Rs. 14. What existence would they lead with that amount? What hopes can you hold for all these weavers unless there is a comprehensive scheme to utilise their talent Now, in this age of synthetic goods which is lording the market, what can they do? Forget what Gandhiji said or the leaders of those days said. We have come about half a century from those days. So, Gandhiji is practically unknown. Gandhiji, Netajai, Nehru and everybody is unknown So, evolve some suitable mechanism for utilising the talents of thse improverished people. Would you ensure that these crores of rupees which you have mentioned here-maybe Rs. 15 crores or something like that-will be properly utilised in order to resuscitate the lives of these weavers? If you can do that, if you have any such scheme, it will be worthwhile. Otherwise, it is a longdrawn Calling Attention Motion. Ultimately it is an infructions one, full of sound and fury and signifying nothing. If that is to be the feeling, the State and the Centre should uniteduly pull their resources and try to evolve a programme in consultation with those who know the matters close enough for the upliftment of these weavers.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): The present tragedy is the outcome of the Government's Textile Policy which was announced on 6th June, 1985. Mr. Ram Niwas Mirdha, the then Minister, soon after he took over the office, within two days, announced that policy without considering the consequences. And on top of it, even after announcing the policy the Government was not serious to implement the same in its true spirit. It was remarked in the report of the Abid Hussain Committee that:

> "We, therefore, feel that 1985 Textile Policy did not address itself adequately to the institutional, financial and other means to acquire, to achieve the objectives it has set itself".

It shows the complete apathy and callousness of the Government to the problems faced by the handloom weavers as well as the cotton growers. These starvation, deaths as well as suicides among these two sectors are the outcome of it. And the Government is the real culprit for the tragedy. A similar situation took place during 1988, when Telugu Desam Party was in power in Andhra Pradesh. But the then Government in Andhra Pradesh defused the situation by opening production centres at Chirala, Bhattiprolu, Cheemakurti, Chebrolu and other places,. They procured yarn and supplied it at subsidised rates. Again they procured finished products to be marketed through APCO. The Social Welfare Department. as well as the governmental agencies were asked to consume that production. But thanks to the performance of the State Government in the State through G. O. 168 by a single stroke of the pen, by a single G.O. 168, they scrapped that And the Social Welfare Department was asked to purchase the cloth from wherever they liked, from wherever they got more commission and kickbacks. This is the tragedy. The hon. Minister in this statement has mentioned that the Government was good enough to sanction Rs. 5000 for each bereaved family and another Rs. 1000 as consumption loan. What a farce? The same Government under the so-called modernisation scheme for the textile industry, for 214 textile mills in this country, sanctioned Rs. 834.64 crores. This is

(Dr. Yelamanchili Sivaji)

called a super soft loan. It charged only 4 per cent interest on the loan to be repaid in 20 years. What a large heart is the Governent having for the textile industry. On the other hand, the Governmnent has given so many concessions for the artificial fibre, for the import of artificial fibre, for the imort of artificial fibre machinery, for their production at the cost of the cotton growers and handloom weavers to benefit the big industries like Vimal and Reliance. Is it not a fact that the Government is sold out to Reliance and Vimal at the cost of the cotton growers and handloom weavers? The Governmnent has accepted the Abid Hussain Committee Report. But they did not care to circulate that report to the Members. They said that they had accepted the report. But they are not serious to implement the same. What a fun the Government is indulging in! I am not able to understand. Sir, there are 300 cases pending in various High Courts challenging the reservations policy, as far as 22 itmes are concerned. But do you know who the counsel was on behalf of the textile industry? Mr. P. Chidambaram, the Minister for Commerce, was counselling for the textile mills to scrap the reservation policy and he successfully pleaded for getting it stayed. And I was told that Mr. Pragata Kotaiah wrote a letter to the Prime Minister to restrain Mr. Chidambaram to plead on behalf of the textile industry which was contrary to the norms of the Government policy. Is it not a fuct that Mr. Chidambaram was the Standing Counsel for the textile industry challenging resrvation of 22 items? This Government is not serious about it. When Mr. V. P. Singh was the Prime Minister, they prepared a draft Bill to be introduced in the Lok Sabha so that these things cannot be challenged in the court of law under the Ninth Schedue. But unfortunately that Government fell. Is it not the duty of the present Government to see that the Bill is introduced? (*Interruptions*).

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharasthra): It was an unfortunate Government.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: It is unfortunate for the people in Andhra Pradesh..(*Interruptions*).

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Your Governmnt made a mess of all the polices.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): We are very much worried about this problem. We are not worried about that Governemnt or this Government. We are very much worried as to where this Governent is leading this country. We are not bothered about the past. We are only worried about the Governemnt in power.. (*Interruptions*). As long as you people have Chidambarams and others, you cannot go anywhere..(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us not take names. Nothing will go on record. Mr. Jadhav, this is not the way. If you talk among yourself, what is the relevane of the Chair? If you want to talk like this, I will vacate the Chair. You must address the Chair and if you have any point to make, you talk to me.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): This is part of liberalistion policy.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, it is very important debate and that is why I requested him to raise the serious points so that the problems of the handloom weavers can be solved. This is not a question of this Government or that Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Let us have the sense of the House. This is a national tragedy. Let us not mix it up.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : That is why I say, it is unfortunate.. .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Now Let us have the fortune of hearing him.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Your Mr. Chidamrabam is also a good friend of mine....

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY : Unfortunately.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : With the liberalisation of the so-called industrial and economic policy, I am very much afraid that the handloom sector is going to face a severe onslaught both from the textile industry and the power loom sector, thanks to the performance of the Government of India headed by the present rulers. With the new industrial policy for textile industry of the medium size, they need not go in for licence. They can open up units with the monetary limit of Rs. 25 crores, and they need not seek any licence. So, the onslaught will be more for the handloom sector hereafter. So I do not see any production in the handloom sector;

I do not see any future for it. I hope the Government is serious about the recommendations announced by the Abid Hussain Committee and implement the same.

Our Dada mentioned about withdrawing export of cotton. But this is not good suggestion and it will not stand the test of scrutiny, because the handloom sector consumes only hank yarn ; they do not consume cone yarn. So, it is the duty of the Government to see that hank yarn is not diverted to power looms or for export. It is a fact that last year -- thanks to the performance of V.P. Singh Government -- 12.25 lakh bales of cotton were exported. But it is not the case and it is not responsible for the tragedy in the handloom sector. The main culprit is the Government of India who is giving so many reliefs to artificial fibre only to benefit and give advantage to the big industrialists like Vimal and people like Mr. Chidambaram and others pleading on their behalf.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : This is not fair. Let us not take names.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : So this is the tragedy. I would like to advise the Government to have come consultation with the Government of Andhra Pradesh and see that proper, necessary reliefs are extended to the handloom weavers. I would like to add that it is necessary that the Minister should make it a point to vist the Guntur District and the Prakasam District. It is not only a tragedy but a shame on a civilised nation and on a civilised Government to have hundreds of people dying of starvation and committing suicides. The Chief Minister, Shri Janardhan Reddy and other State Ministers say that those deaths were not due to starvation but due to alcohol. I believe only those Ministers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : That is what I asked you, whether it was really due to starvation.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Probably those Ministers who are under the influence of alcohol would say this. Thankyou.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश स्वयं प्रधान मंत्री जी का प्रदेश है और वहां कांग्रेस की सरकार है । वहां के बुनकरों की मुसीबत और मौतों की ओर श्री कोटैया समेत इस सदन के माननीय सदस्यों को ध्यान पड़ा है, यह बात का सबूत है कि सरकार बिल्कुल जड़ है चेतनाशून्य है और कर्तव्यहीन इस सवाल से जुड़े हुए कुछ और भी सवाल हैं जो पूरे देश को छूते हैं और मैं चाहता हू कि उनकी तरफ आपका और सदन का ध्यान खींचा जाए ।

महोदय, एक सवाल तो यह है कि यहां के बुनकर मुश्किल से प्रति दिन, प्रति व्यक्ति 2 रुपए कमाते हैं और उनको जो भोजन मिलता है वह सिर्फ अनाज के रुप में मात्र तीन-चार छटांक मिलता है, जिसमें न सब्जी है, न दाल है और दूध का तो सवाल ही नहीं उठता । यह भोजन उनको मिलता है और यह भोजन पाने वाले आदमी में काम करने की शक्ति कितनी रह जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं । आज हमारे देश में यह हो रहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं ,गरीबी और कुपोषण के नाते उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि उनमें काम करने की शक्ति नहीं रह गई है और यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है । इस स्थिति के चलते किसी भी क्षेत्र में पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती । यह इतना बड़ा सवाल है । और सरकार के ऊपर इन चीजों का असर नहीं पड़ता है ।

महोदय, इतना अपर्याप्त भोजन, इतना कुपोषण, कि आदमी में काम करने की शक्ति न रह जाए, यह आज पूरे देश की हालत है । यह केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है । यह एक बड़ा सवाल है । दूसरी तरफ जो मौतें हुई हैं, उनका सरकार मखौल उड़ा रही है और यह कह रही है कि ये मौतें भुख से नहीं हुई हैं । मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भूख से मौत एक दिन में नहीं होती, भूख से मौत होती है तिल-तिल करके । भूख से आदमी तिल-तिल करके करके मरता है ,घुल-घुलकर मरता है । उसको खाना नहीं मिलता है जिससे बीमारी का जन्म होता है और बीमारियां कुछ लोगों ने गिनाई हैं, जैसे पीलिया है, तपेदिक है इनसे लोग मरे हैं और सरकार

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

इतना ही कह देती है कि ये नैसर्गिक मौतें हुई हैं और भूख से मौत नहीं हुई है । तो क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि इसकी जांच हो या इसके लिए कोई कमेटी बैठाएगी जो यह तय कर दे कि भूख से मरने वाले धीरे-धीरे मरते हैं और लंबे अरसे तक भूख चलती है जिससे वह मरते हैं । इस क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ है और सरकार ने माना है कि मौतें हुई हैं । बताया गया है कि 73 मौतें हुई हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं । कुछ लोग मरने की स्थिति में हैं । तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए था, ईमानदारी इसी बात में थी कि सरकार स्वीकार करती कि ये मौतें भूख से हुई हैं क्योंकि उनको लंबे अरसे तक सही खाना नहीं मिला था ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास किसी भी दूर दराज के इलाकों की जानकारी हासिल करने के लिए अब पर्याप्त साधन है। जहां तक इस प्रकार की मौतों का सवाल है, अगस्त से तो अखबारों में आने लगा था, अगस्त से यह चीज प्रकाश आने लगी थी कि लोग वहां भूख से मर रहे हैं और इतने दिनों में सरकार का ध्यान नहीं गया। जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया तब सरकार ने समीक्षा करनी शुरू की। माननीय मंत्री जी जो आपका वक्तव्य है इससे निराशाजनक और कोई वक्तव्य हो ही नहीं सकता। एक तरफ लोग भूख के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं और बेकारी, गरीबी के कारण मर रहे हैं और दूसरी तरफ आप समीक्षा कर रहे हैं। अब आप ऐक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से उनको रिलीफ दिया जाए। पहली रिलीफ जो मंत्री जी ने गिनाई है वह यह है कि जो बुनकरों का बकाया था वह उनको दिया जाए। जो उनको मिलना चाहिए था वह उनको न मिलने के कारण उनकी हालत खराब हुई है, वह पैसा आप उनको देने जा रहे हैं। वह भी पूरा पैसा आप नहीं देंगे। जैसे श्रीमती सुषमा जी ने बताया था पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ अंश उसका भुगतान करने जा रहे हैं। यह पहला एहसान आपने उन पर किया है।

दूसरा एहसान उन्होंने यह किया है कि वहां की सरकार को भी कह दिया है कि पैसा दे दो। अपनी तरफ से ये सबसिडी देने जा रहे हैं जो कि बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। यह सभा जानना चाहेगी कि इन पैसों के भुगतान के लिए देरी क्यों हुई। उनको समय से पैसा क्यों नहीं दिया गया? जब आप जवाब देंगे इस ध्यानाकर्षण का तो इस बात पर रोशनी डालें कि सबसिडी और उनका जो बकाया पैसा था वह उनको समय पर क्यों नहीं दिया गया?

तीसरा एहसान उसी पैरे में ये करते हैं कि 5 हजार रुपया हर मृतक के परिवार को उन्होंने दिया है। सभी लोगों ने कहा है, माथुर साहब ने भी कहा कि यह पैसा बहुत कम है। मैं भी अपनी आवाज उनको साथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि यह सचमुच कम है, इसको बढ़ाइए।

इसके साथ ही जो आप उनको लोन देने जा रहे हैं यह इंटैरेस्ट फ्री होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की बात का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस को इंटैरेस्ट फ्री कीजिए। आज आपको प्यास लगे और तब आप कहिए कि कुआं खोदिए जब यह मुसीबत आ गई तब आपको याद आया इससे कुछ होता नहीं है। इसको आप आगे बढ़ाइए, इसके लिए आप इंतजाम कीजिए। दूसरे आप व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो प्री बजट रेट था उस पर उनको माल मिले। मिलेगा या नहीं, इसमें भी मुझे शक है। क्योंकि यह सूत के दाम पिछले कई सालों से बराबर बढ़ते रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यह छलांग लगा रहे थे। जब से पिछला बजट आया है तब से बेतहाशा बढ़े हैं। वह सामान जिससे बुनकर अपना कपड़ा तैयार करता

है वह बराबर महंगा होता चला गया और दूसरे उसकी सप्लाई भी जरूरत भर की न हो, जैसे 460 मिलियन के. जी. की उनकी मांग है, यह मोटा सा अनुमान है लेकिन इनको मुश्किल से 165–170 मिलियन के. जी. सप्लाई होता है। यह दो-तिहाई का गैप बहुत बड़ा गैप है। जब यह हालत रहेगी तो उसके दाम ही बढ़ेंगे और ब्लैक मार्किटिंग भी होगी।

जितनी आपकी सोसाइटियां हैं, सहकारी समितियां हैं उनकी क्या हालत है, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं कि सहकारिता का मतलब ही भ्रष्टाचार है। जो भी सहकारिता के माध्यम से आप सामान बांटते हैं वह बुनकरों तक पहुंचता ही नहीं है। वह ब्लैक मार्किटिंग में चला जाता है। मैं चाहता हूं इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए और इसका निराकरण किया जाए। मेरा कहना यह है कि जब यह कानून बना हुआ है कि 50 परसेंट धागा जिसको हैंक यार्न कहते हैं यही उसमें काम आता है बुनकरों को देने के लिए बनाया जाए तो यह 50 परसेंट वाली शर्त ये मिलें क्यों नहीं पूरा करती? आपके कानून का पालन न हो और आपको गुस्सा भी न आए यह हैरत की बात है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि जो ऐसी डिफाल्टिंग मिलें है उनकी लिस्ट बताइये। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उनको उनका हिस्सा पूरा मिले यह आपका कर्तव्य है। आप इस पर प्रकाश डालिये कि उनको जरूरत भर का सूत क्यों नहीं मिलता? आप एक्सपोर्ट भी कर देते हैं और जो पावरलूम सेक्टर है उसको भी दे देते हैं जो इन गरीब बुनकरों पर तो मार पड़ेगी ही। इससे भी बड़ी मार तब पड़ती है जब सूत के दाम बढ़ते हैं बुनकरों की मजदूरी कम कर दी जाती है। इनकी मजबूरी का एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं और यह सब सरकार की नीति का नतीजा है। उन नतीजों से निपटना भी सरकार का काम होता है। सरकार ने इसमें जो भारी कटौती की है और इंसानी जानें गई हैं तो यह सरकार ऐसे अपराधी से कम नहीं है जो कत्ल करे। (समय की घंटी) अभी तो शुरू किया है मैंने।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude. Your time is over. I know the subject is strious and very tragic.

श्री अनंत राम जायसवाल: मेरा यह कहना है कि उनको जरूरत भर का सूत भी नहीं मिलता। आप सदन के माध्यम से गारण्टी दें कि जो इसके शिकार हैं उनको जरूरतभर का सूत मिलेगा। प्री बजट दर भी कोई सस्ती दर नहीं है। इस ध्यान में रखें जिसकी ओर दूसरों ने ध्यान खींचा है। जो बुनकर कपड़ा बनाते हैं उसको गरीब लोग ही पहनते हैं। यह कपड़ा जितना ज्यादा बनेगा उतना ही उनको लाभ होगा। ऐसे कपड़े की कंजप्पशन बराबर हमारे यहां घटती चली जा रही है। गरीब आदमी की खरीदने की शक्ति घट गई है। वह नहीं खरीद पाता। पर-कैपिटा कंजप्पशन ईयर बाई ईयर घटता चला जा रहा है। उस कपड़े को सस्ता बिकना चाहिये। इसलिये कोई ऐसी नीति बनाइये जिससे गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि प्रोफिट फ्री कास्ट पर उनको सूत दिया जाय लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रीजनेबल प्राइस पर उनको दिया जाये। जो काटन प्राइस है, जो मैन्युफेक्चर पैसा लगाता है धागे पर, उन सबका हिसाब-किताब ठीक करके जो मुनासिब रेट आये उस रेट पर उनको यार्न दिया जाये। जितनी उनकी जरूरत है उतना दिया जाय ताकि पूरे साल अपनी मेहनत से काम करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। यह एक तरीका है उनको पुनर्वास 5 P.M. किये जाने का। वरना वे बराबर मरते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में मौतें हो गई, इसलिये मामला

[श्री आनन्त राम जायसवाल]
प्रकाश में आ गया। यह स्थिति कमोवेश पूरे देश में है। यह जो गरीबी और विपन्नता की हालत है या कुपोषण की हालत है, यह खाली बुनकरों को नहीं छुती है वह देश में अन्य लोगों को भी छूती है जिससे देश की श्रम शक्ति नष्ट होती जा रही है। मैं इसी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता था।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक यह जरूरत पूरी नहो जाए, बराह मेहरबानी आप एक्सपोर्ट को रोक दीजिये। आप एक्सपोर्ट का हल्ला रोज करते हैं, नई नीति बनाते हैं और कहते हैं कि खूब पैदावार करेंगे, बड़ी पैदावार करेंगे और चीजें बाहर भेजेंगे। लेकिन हम जानते हैं, आप नहीं भेज पायेंगे। आप बाहर से जो कर्जा लेते हैं वह कर्जा तो निपटान में, सूद वगैरह में, चला जाता है। अभी आपने जो कर्जा लिया है वह भी इसी तरह से चला जायेगा। इसलिये आप घर की जरूरतों पर ध्यान दीजिये। आपके पास क्या है? आपके पास ट्रेक्टर्स नहीं हैं, आपके पास तोप नहीं हैं, आपके पास जहाज नहीं हैं, तो आप क्या भेजेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या भेजने की सोच रहे हैं? आप रूई भेजेंगे, आप चमड़ा भेजेंगे, आप अनाज भेजेंगे, फल भेजेंगे। आप ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट की जो चीजें हैं वही भेजेंगे। आप थोड़ा इसका मोह छोड़ दीजिये। देश की दुर्दशा को देखते हुये कम से कम जो रूई का एक्सपोर्ट है और धागे का एसक्पोर्ट है उसको हटा दीजिये। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को मार्केट नहीं मिलता है। उसका कोई प्रबंध भी नहीं है। यह सिर्फ एक प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। ये लोग जो समान तैयार करते हैं वह सामान उठता नहीं है, बिकता नहीं है। परिणाम यह होता है कि इनको पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिये मार्केटिंग का प्रबंध किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे इस मामले की तरफ ध्यान दिलाने की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिये सरकार थोड़ा सचेत रहे, यही मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दो बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं श्री कोटैया जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में बुनकरों के साथ जो घटनायें घटित हो रही हैं, वहां पर जो परिस्थिति है, उसके संबंध में ध्यान दिलाया है, और आज यह विशेष चर्चा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि बुनकरों की समस्या, हैंडलूम सेक्टर की जो हालत है, वह आंध्र प्रदेश में जो घटनायें हो रही हैं उन तक ही सीमित नहीं है। यही स्थिति कमोवेश पूरे देश की है। दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में लोग मर रहे हैं और मत्यु होने के कारण बात सामने आई है, लेकिन दूसरे प्रांतों में लोग मरने के वास्ते में हैं और अभी बात सामने नहीं आ रही है। माननीय सदस्यों ने जिन बातों को कहा है, मैं उनको न दोहराते हुए केवल एक दो बातें जोड़ना चाहती हूं। अभी अभी हमारे देश में कुछ घटनायें घटी हैं, जैसे बनारस में दंगा हुआ और बनारस के दंगों में जो लोग प्रभावित हुये वे बुनकर हैं और बुनकरों में भी ज्यादातर मुसलमान हैं। आप जानते हैं कि बनारस के बुनकर बेहतरीन साड़ी और सिल्क के कपड़े वगैरह बनाते हैं जिनके वगैर किसी घर में शादी और पर्व-त्यौहार के काम नहीं होते हैं। आज स्थिति यह है कि दंगों के बाद वह घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बुनाई की हालत में बात में आयेगी, लेकिन अभी वे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनका कारोबार ठप्प हैं और वे भूखमरी के कगार पर हैं। मेरे प्रांत बिहार में भी दंगा हुआ था और यह भागलपुर में हुआ था। दंगों के कई साल बाद भी बुनकरों की स्थिति जैसी पहले थी वह आज तक नहीं हो पाई है। वे भागलपुर का टसर सिल्क बुनते थे। यही हालत बनारस की है और वही स्थिति दूसरी जगहों की भी है। हमारे बी०जे०पी० के भाई

मुझे यह कहने के लिये माफ करेंगे कि वे राजनीति से प्रेरित हो कर ये दंगें करा रहे हैं। इन दंगों के कारण बुनकर बरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और उनके कारण उनकी हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जायेगी उनके लिये केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित नीति का निर्धारण करना चाहिये कि हैंडलूम सेक्टर में हमको क्या करना चाहिये क्या हैंडलूम को अपनी मौत करने दिया जाये ? अगर हैंडलूम वीवर्स बुनकरों को अपनी मौत करने देना है तो यह भी तय कर दीजिये कि उनके मरने के बाद उनको पांच हजार तीन हजार दो हजार उनकी जिन्दगी की जो कीमत आप लगाना चाहें लगायें कि इतना दे देंगे। लेकिन अगर आपको इस प्राचीन परम्परा को जीवित रखना है यह हमारी कला और संस्कृति का अंग है इसको अगर जीवित रखना है यह जो हाथ का हुनर है इसको अगर जीवित रखना है तो इसके बारे में हमें निश्चित रूप से दिशा-निर्देशन देना होगा। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिशा-निर्देशन में आपको निश्चित रूप से यह तय करना पड़ेगा कि हैंडलूम सेक्टर को हम कम दाम में सीधे सूत उपलब्ध करायें किसी बिचौलिये के जरिये नहीं। क्योंकि बिचौलियों के जरिये उनके पास जो सामान जाता है कच्चा माल जाता है, धागा जाता है, उनके बारे में उनको पता नहीं हो पाता है। जो बनारसी सिल्क की साड़ी बाजार में दो हजार में बिकती है, उसको बुनने में बुनकर को काफी समय लगता है, लेकिन उनको उस बुनकर को बहुत ही कम पैसा मिलता है। यह मैंने असम में भी देखा है, अपने प्रांत में भी देखा है और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में भी देखा है। इसलिये सरकार को सीधे बुनकरों को धागा उपलब्ध करना चाहिये और जो माल तैयार हो गया है जो उत्पादित माल है उसके मार्केटिंग की पालिसी को भी गवर्नमेंट को तय करना चाहिये। उसके लिये मार्केटिंग पालिसी कैसी हो उसके लिये किस तरह से यह ठीक हो यह गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। मैं जानती हूं कि हैंडलूम वीवर्स की जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं यह भी वेस्टेड इन्टरेस्ट का अड्डा बन गई है। इनके कारण उनका शोषण होता है। इस शोषण से उनको मुक्त करने के लिये सही मायनों में मार्केटिंग पालिसी क्या हो इसके बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये।

महोदय एक बात जो गवर्नमेंट कर सकती है वह यह है कि गवर्नमेंट यह फैसला करे कि जितने भी गवर्नमेंट उपक्रम हैं, जितने भी गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं जितने मकान हैं जितने दफ्तर हैं इन सभी जगहों पर हैंडलूम से बनी चीजों की ही इस्तेमाल हो। यह तो आप कर ही सकते हैं। पर्दा हैंडलूम के लगा सकते हैं सोफा कवर इसके लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो इससे इस उद्योग को काफी राहत मिलेगी। इसलिये सरकार को एक निश्चित दिशा निर्धारित करके हमने आगे चलना चाहिये। अगर हम इसी तरह से समय समय पर उनको जो परेशानियां हो रही हैं इसका रोना आपके सामने रोयें और यह ऐसे ही चलता रहे तो इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार एक निश्चित दिशा-निर्देश तय करके इस बारे में एक नयी पालिसी लेकर सामने आयें और वह सदन को बतायें कि सरकार उनके बारे में क्या करना चाहती है। हैंडलूम सेक्टर को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? सरकार उनको अपनी मौत मरने देना चाहती है या उनको जीवित रखना चाहती है ? अगर जीवित रखना चाहती है और सरकार उनके लिये एक नयी नीति तय करना चाहती है एक निश्चित नीति निर्धारित करके उनको राहत पहुंचाना चाहती है तो सरकार इस बात को यहां सदन में स्पष्ट करें। महोदय, मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद।

प्रो० आई० जी० सनदी (कर्नाटक) : आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब, भारत की कला सौंदर्य बुनाई को जीवित रखने वाले, खून पसीना बहाकर ईमानदारी

[श्रीआई० जी० सनदी]

की रोटी खाने वाले करघा बुनकरों की हालत चिंताजनक है । उनका पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गये हैं। उनक जीना मरना समान हो गया है । आज उनके पास बुनने के लिये धागा नहीं है । उन्होंने अपनी आंतों के धागे का ताना बनाया है और अपनी सांसों का बाना बनाया है । इसके कारण उनकी जीवन की चदरिया फट गई है । ऐसी स्थिति में दुखी आंध्र के बुनकरों के संकट की घड़ी में मानवोचित सहायता जो केन्द्र सरकार ने की है, उनकी भलाई के जो कार्यक्रम बनाये हैं, वह सराहनीय है ।

महोदय, हथकरघा उद्योग एक असंगठित उद्योग है । संपूर्ण देश भर में यह उद्योग फैला है । इस उद्योग की विशेषता यह है कि यह देश की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है । कृषि के बाद रोजगार देने वली क्षमता रखने वला यह एक दूसरा क्षेत्र है । देश में समस्या कपड़ा उत्पादन का लगभग 27 प्रतिशत हथकरघा क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाता है । इस क्षेत्र में अधिकांश वे लोग कार्य कर रहे हैं जो समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग से आते हैं । महिलायें जिनकी प्रगति के लिये सरकार सतत प्रयास कर रही है, अधिक से अधिक रोजगार इस क्षेत्र में महिलाओं को मिलता है । इस उद्योग का संबंध हमारी राष्ट्रीय भावना और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से भी है । हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि उन्हें इस उद्योग की आर्थिक शक्ति का पूरा ज्ञान था । चरखा जन-शक्ति का प्रतीक था और आज भी है । इसका संबंध कम्पोजिट कल्चर से जुड़ा हुआ है । कबीर साहब भी इसी भावना से प्रणेता थे । यह उद्योग हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसलिए इस उद्योग को पार्टी दी जानी चाहिय । इस उद्योग में लगी हुई महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना हमारा फर्ज है, कर्त्तव्य है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज करघों पर काम करने वाले बुनकरों की हालत बहुत दयनीय है । सभी राज्यों में यह हालत है कि उनके उपकरण पुराने हो गये हैं, उनको पावरलूम से कम्पीटीशन करना दुश्वार हो गया है । उचित दाम पर कपड़ा बेचना बहुत कठिन हो गया है । शिक्षा का अभाव है । सिल्क यार्न और केमिकल्स महंगे हो गये हैं । सस्ता हो गया है उनका जीवन और उनकी जान ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में यह उद्योग धंधे चलते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर्ज को बुलाया जाये और इस बारे में जो कार्यक्रम तथा योजनायें केन्द्र सरकार की हैं उनसे उनको परिचित कराया जाय । इतना ही नही जो इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, उन सब की एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जायें जो थोड़े दिनों में अपनी रिपोर्ट दे दे, उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये एक नयी टैक्टसाइल पालिसी बनाई जाये । इस सुझाव के साथ, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, में आपको तहेदिल से धन्यवाद समर्पित करता हूं ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : The plight of the handloom weavers has laready been explained by the hon. Member and the mover of the motion, a very senior Member and who is in the field, Shri Pragada Kotaiah. In Tamil Nadu and also in my State lakhs of workers are being involved in this business. Their job is only to weave the cloth on the basis of the yarn supplied either by the cooperatives or by the private individuals, who are middlemen, and who are dealing in this business—the master weavers. Most of its finished product goes to Singapore and to other countries and the Government is earning a very good amount of foreign exchange out of it. But the unfortunate part is that the plight of those handloom weavers is going from bad to worse. In spite of the fact that the new textile policy was introduced by our leader, late Shri Rajiv Gandhi, it was not given effect to as far as the handloom weavers are concerned. The exicse duty exemptions which were given to the handloom weavers was taken by the powerloom sector and the textile mills. The only way open to the hon. Minister to give protection to these weavers is through cooperatives. Even in cooperatives there are some lacunae. We find the persons who are at the helm

of affairs, the officers, are not supplying yarn to them and they are encourging only one section of the people. There fore, to strengthen the cooperative system, the State Governments may be advised suitably to have a watch on the functioning of the cooperative societies as far as the handloom sector is concerned.

Secondly, the insurance scheme which the hon. Minister has envisaged should be extended t all the weavers. Experimenting it with only one section is not going to help the starving weavers. Therefore, the insurance scheme for them is a must. The hon. Minister has given details about the housing scheme for them. It has already been implemented in some States, but only 70 per cent of the employees are getting the benfits. It may be extended up to 50 per cent of the persons who are engaged in that particular trade. Above, all, my submission is that the matter is pending before the court. The relief that is to be given to the handloom weavers has been stayed by the State High Courts. My point is that the Minister should take up this matter personally and see that the stay is vacated so that the 22 items that have been earmarked exclusively for the handloom sector are enjoyed by them and their burden is lessened. I say this because in the international market and in the national market there is a total competition and the handloom weavers are not able to compete with the powerloom sector and the textile mills. Therefore, the benefits meant for them should go go to them only. For that I want the Minister to allocate more funds. The funds which have been provided by way of subsidies are not sufficient. More funds have to be provided to them. The condition of the handloom weavers day by day is going from bad to worse. Therefore, to save the handloom weavers from starvation, it is time for the Minister and the Government to act and review the textile policy so that more benefits can be given to them. With these words, I thank you.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं दो तीन सवाल करूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : What do you want to ask? Everybody has expressed his point. He will cover every point. Let us hear him.

श्री राम नरेश यादव : मैं जो जानना चाहता हूं, वही पूछ रहा हूं आपके माध्यम से । महोदय, यह बहुत ही चिंता का विषय रहा है जिस तरह से कि आंध्र प्रदेश से सारी घटनायें हुई हैं । एक तरफ तो हमारी सरकार की आर्थिक पालिसी स्पष्ट हो गयी है, इंडस्ट्रियल पालिसी स्पष्ट हो गयी है, कमर्शियल पालिसी भी स्पष्ट हो गयी है । 1985 में जो टेक्सटाइल नीति आई थी वस्त्र की वह तीन साल के लिये थी, आज 1991 चल रहा है, बदली हुई परिस्थिति के लिये कि टैक्स टाइल का हैंडलूम से कितना संबंध है, किस तरह से इस नीति ये है, उस बारे में मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि आज के परिवेश में जो सारी परिस्थितियां देश की बदल गयी हैं, आर्थिक वातावरण दूसरी तरफ का हो गया है उसको ध्यान में रखते हुये वस्त्र नीति को एक नयी दिशा देने का का क्या आप करेंगे... (**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Let us hear him.

श्री राम नरेश यादव : दूसी बात, आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट इसलिये मंगायी थी, सरकार ने इसलिये रखी थी कि उस रिपोर्ट के आधार पर वस्त्र उद्योग विशेष रूप से हैंडलूम सेक्टर को बहुत ही आगे बढ़ाने की दिशा में क्या क्या कार्यवाही की जायेगी, क्या क्या कदम उठाये जायेंगे । इसलिये उस कमेटी को बैठाने का काम किया गया था । उस कमेटी ने सर्वे किया था, अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद 1990 में अपनी रिपोर्ट भी दी थी । मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार डेढ़ साल तक रही उसने कुछ नहीं किया और आज भी सरकार के सामने वह रिपोर्ट पड़ी हुई है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के कितने दिन के पश्चात जो उसकी सिफारिशें हैं बुनकर उद्योग के क्षेत्र में, हैंडलूम के क्षेत्र में उनको कब तक लागू करने का काम करेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : उनको पहले सुन लीजिये

श्री राम नरेश यादव : तीसरा सवाल है कि महोदय आज कम्पटीशन का युग है । हैंडलूम सेक्टर में जो कपड़ा बनता है, पावरलूम में जो बनता है, मिलों के क्षेत्र में जो बनता है इनकी प्रतिस्पर्धा में हैंडलूम क्षेत्र में बना हुआ कपड़ा मुकाबला नहीं कर सकता है । इसलिये सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ विचार करके 22 आइटम्स ऐसे रख थे जो केवल हैंडलूम सेक्टर में बनेंगे । आज वह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2–3 साल से पेंडिंग है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे उस दिशा में ऐसी कार्यवाही करेंगे कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाय और जो 22 आइटम्स उस क्षेत्र में रखे गये हैं वे उस क्षेत्र में बन सकें और प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें । चौथा, मेरा कहना यह है कि सिल्क उद्योग भी संकट में है । इसका भी यार्न नहीं मिल पा रहा है । मैं चाहता हूं कि आप सिल्क यार्न को भी उपलब्ध करा दें ताकि 40 लाख बुनकर जो आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों में लगे हुये हैं वे इससे लाभांवित हो सकें । यही मैं जानना चाहता हूं । (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNA JI MASODKAR) : Please listen to the Minister. You have already spoken. Please sit down.

श्री अनन्त राम जायसवाल : सूत के धागे की पैदावार की जितनी स्पिनिंग मिलों की पैदावार गिर रही है । इटावा का मिल अभी हमको अर्जुन सिंह भदौरिया जी ने सूचना दी कि बन्द पड़ा है । क्या इसको फिर से चालू करवा देंगे... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Minister, you have seen the mood of the House. The level of poverty which handloom weavers are subjected to is a matter of prodfound concern to this House. Members of all parties have urged upon you to improve their condition. This issue is not of any partisan nature. I would request the Government and particularly you, to respnd to the points raised by the Members. The whole House shares the anxiety of the hon. Members. Now, Mr. Minister

SHRI V. NARAYANASAMY : Thank you very much, Sir.

SHRIMATI KAMLA SINHA : Thank you ,Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : They are really feeling anxious about their plight.

श्री अशोक गहलोत : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गम्भीर विषय और चिंताजनक स्थिति पर ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव इस सदन के वह देश के वरिष्ठ नेता श्री पी० कोटैय्या जैसी हस्ती के माध्यम से वह अनेक अन्य सदस्यों के द्वारा रखा गया है । यह एक शुभ संकेत है कि इतने सीनियर मेंबर जो अपनी जिंदगी का कमिटमेंट है लूम के साथ रखते हैं और अन्य करीब-करीब पन्द्रह माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया । अधिकांश लोगों ने, मैं समझता हूं कि अगर कुछ को छोड़ दें, तो उन्होंने जो भावना अपने प्रकट की, उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी बात कही थी, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है ।

इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा था कि बजाए इस विवाद में जायें कि यह मौतें जो हुई हैं, यह भूख से हुई हैं या कोई अन्य कारणों से हुई हैं, जैसा कि राज्य सरकार का मत है कि यह मौतें बीमारी से भी हुई हैं, वृद्धावस्था से भी हुई हैं, उनका अपने घर की समस्या के कारण आत्महत्या से भी हुई हैं । पर मैंने इस बिंदु को टच नहीं किया है और मैंने सीधा कहा कि इस सवाल में जाने की बात नहीं है ।

सवाल यह है कि जहां वीवर्ज का कंसेंट्रेशन है, वहां पर अधिकांश मौतें हुई हैं । उत्तर प्रदेश से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही थी । मैं उससे अपने सहमति व्यक्त इस तौर से करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पश्चिमी राजस्थान से, उसके बारे में भी यहां कई बार चर्चा हो चुकी है और तब पूरे देश का ध्यान आकर्षित होता है जब वहां पर पांच-छह साल लगातार अकाल और सूखा पड़ता है, तब उसकी बड़ी खबरें आती हैं कि तीन सौ, चार सौ, पांच सौ लोग भूखे मर गये ।

इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि भूख से मौत का मतलब यह नहीं कि कोई भूख से तड़प कर मर रहा हो और उसको पड़ौसी कोई खाना नहीं दे रहा हो। भूख से मरने का तात्पर्य जो मैं समझता हूं और प्रागदा कोटैय्या जी का भी जो होगा, वह इस सेंस में होगा कि आज बुनकरों की माली हालत ठीक नहीं है, जिसके कारण उनकी रेजिस्टेंस पावर शरीर की खत्म हो जाती है। इसलिए वह बीमारी झेल नहीं पाते और इसलिए हो सकता है कि वह भूखे मरने की बात के रूप में सामने आती हो।

मेरी ऐसी मानना है कि यदि आज हम सर्वे करें, तो खाली आंध्र प्रदेश की ही बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई प्रदेश मिलेंगे जहां पर ज्यादातर बुनकर रहते हैं, जो गरीबी की हालत में रहते हैं, उनकी हालत भी ऐसी ही आपको सर्वे कराने पर ज्ञात हो सकती है।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस इशू को इस रूप में देखना नहीं चाहते कि भूखे मरे और सरकार और राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, या कोई सरकार कुछ करना नहीं चाहती मैं सब से पहले तो आपके माध्यम से इस सदन को और इस सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार, जैसे शुरू में ही इस बात को ध्यान में रखे हुए है कि हथकर्घा उद्योग हमारे देश की संस्कृति और देश की परंपरा को सामने रख करके उसको मजबूत करने वाली बात सामने रखनी है और जो हमारे बुनकर भाई उसमें काम करते हैं, उनकी जीविका कैसे सुधर सके, इस बारे में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि भूख से मरने की खबरें पहले भी आई हैं, 1988 से भी सुन रहे हैं। उस वक्त भी करीब 30-35 लोगों के मरने की खबरें आई थीं। तब से लगातार यदा-कदा भूख से मरने की खबरें आ रही हैं। अभी हाल ही में जब पिछला सेशन चल रहा था, आपको मालूम होगा कि इस सदन में जब इस मिनिस्ट्री पर चर्चा हो रही थी, तब भी यह सवाल उठा था और मैंने ही आश्वासन दिया था कि हम लोग केन्द्र की एक टीम भेजेंगे और वह वहां जाकर के तथ्यों का पता लगायेगी। हमने दो टीमें भेजीं और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ में उन्होंने वहां पर दौरे भी किये।

इसलिए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जब लोग मर गये, तब सरकार ने कुछ कार्यवाही करने का जो हमने वक्तव्य दिया है, उसमें कुछ घोषणायें की हैं। ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है। हमने तब से ही जब यह जानकारी मिली कि पूरे देश में यार्न को लेकर के प्राईसेज बढ़ रही हैं और वह एक सीमा से अधिक बढ़ रही हैं और यह भी खबरें आ रही थीं कि काटन की प्राइसेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, आपको मालूम है कि काटन की प्राइसेज इस साल पिछले साल से बिलकुल डबल हो गई थीं और इसका कारण क्या है, वह भी आपसे छिपे हुए नहीं है। कई बार जब एक गलत वक्त पर हम लोग कोई एक्सपोर्ट की घोषणा कर देते हैं, वह भी एक बड़ा कारण बन जाता है, चाहे हमारे किसानों को तो उसका कोई फायदा मिला नहीं और ट्रेडर्ज को उसका फायदा मिला अभी जून-जुलाई तक जाते-जाते उसकी प्राइस बल हो गई थी। इसलिए यार्न की प्राइस बढ़ना स्वाभाविक था। पर हमें लोगों ने उसके बावजूद भी बिना समय बर्बाद किये हुए अविलम्ब कदम मैं उठाये, जिससे कि यार्न की प्राइस को कैसे रोका जर सके। एन.टी.सी. के माध्यम से हम लोगों ने सूत की सप्लाई करने का काम एकदम प्रारंभ किया और जहां-जहां बुनकर केन्द्रीय क्षेत्र थे वहां पर सूत के डिपो भी खोल दिए गए थे। इसके साथ में एन.टी.सी. जो सरकार उपक्रम है उसको अविलम्ब आदेश दिए गए कि आप जो 40 काउंट से अबव काउंट के यार्न रहे हैं उसको बजाय आप 40 और बिलो काउंट के यार्न बनायें जिससे बुनकरों

[श्री अशोक गपलोत]

में जो काम आता है हैंक यार्न के रूप में उनको लाभ मिल सके । यह कार्यवाही भी अविलम्ब की गई और यह भी कहा गया कि आप सूत के डिपो एन. टी. सी. खुद खोलें और साथ में मिल रेट पर वह अपने विक्रय केन्द्र की बिक्री शुरू करें । सूत वितरक जो सूत का भंडार एकत्र न कर सकें उसके लिए भी हमने टक्सटाइल कमिश्नर को यह निर्देश दिए कि आप डी-होर्डिंग कैंपेन चलायें, कहीं पर जो ट्रेडर्ज हैं वह सूत का होर्डिंग कहीं नहीं हो पाए जिससे कि उसके दाम बढ़ रहे हों । हमें मालूम था कि बैलेंस आफ पेमेंट्स की स्थिति देश की क्या है और हम लोग चाहते थे कि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा देश को हासिल हो । उसके बावजूद भी, क्योंकि उपसभाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि जैसा अभी सदस्य चिंता प्रकट कर रहे थे कि बुनकर और हैंडलूम का जो सैक्टर है वह इस प्रकार का विकेन्द्रित सैक्टर है कि जहां करीब एक करोड़ से अधिक लोग तो अपनी रोजी कमाते हैं और यह कोई इस प्रकार का संगठित क्षेत्र नहीं है जो कि मिल सैक्टर की तरह या दूसरे सैक्टर की तरह अपनी आवाज को पहुंचा सके । इसलिए हमने इन लोगों की समस्या को देखते हुए यहां तक भी किया कि जो हमारे कमिटमेंट थे 100 मिलियन किलोग्राम यार्न बेचने के, उसके बावजूद भी हमने । टैंपोरेरी रूप से यार्न के एक्सपोर्ट को सस्पेंड किया । उसको ले करके जैसे हमारे वरिष्ठ सदस्य कुलकर्णी साहब बोल रहे थे, इसको ले करके कई तरह की आलोचनाएं भी हुईं । कई लोगों ने यह कहा कि यह आपने अच्छा निर्णय नहीं किया इससे हमारे देश के जो कमिटमेंट थे वह पूरे नहीं हो पायेंगे और एक बार कमिटमेंट जब समय पर पूरे नहीं होते हैं तो आगे आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट करते वक्त तकलीफ आती है । उसके बावजूद भी हमने बुनकरों के हित में अविलम्ब यह कार्यवाही भी की थी ।

इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार ने यह कदम उठाए और दूसरी तरफ हमने सारे मुख्य मंत्रियों को टैलेक्स के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और पत्र लिख करके उनसे निवेदन किया कि आप अपने स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट की जो मिलें हैं कोआपरेटिव सैक्टर में भी हैं स्टेट एंटरप्राइजेज के अन्दर हैं, उनके माध्यम से भी आप एन० एच० डी० सी० के जरिए अधिक से अधिक हैंक यार्न उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की आप व्यवस्था करें । हमने यह भी निवेदन किया कि आप अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से यह भी ध्यान रखें कि कोई सूत होर्डिंग नहीं हो रहा हो और वहां के जो स्टेट लेबल के जो हैंडलूम कार्पोरेशन थे उनके माध्यम से भी सूत के डिपो खोलने का काम भी हम लोगों ने उस वक्त में किया था । इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने कोई असर नहीं छोड़ी कि किस प्रकार से यार्न उपलब्ध हो सके और उचित दाम पर उपलब्ध हो सके । जहां तक यार्न की सप्लाई की बात है, उसकी उपलब्धता की बात है, मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें कोई यार्न उपलब्ध हो रहा है सवाल इस बात का है, प्रागदा कोटैया साहब कह रहे थे कि यार्न हैंक यार्न की फर्म में बहुत कम मार्केट में आया है, जो फिगर्ज उन्होंने दिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हैंक यार्न आब्लीगेशन स्कीम जो बनी हुई है एक आदेश के तहत उसमें जो मिलें यार्न बनाती हैं उसका खुद का अपना उपयोग वह छोड़ने के बाद थे और हौजरी में जो काम आता है उसको छोड़ने के बाद में जो यार्न प्रोडक्शन होता है उसका 50 परसेंट का आब्लीगेशन आज देश के अन्दर है और जो फिगर्ज हमारे पास हैं उसके माध्यम से करीब 48 परसेंट मार्केट में उपलब्ध इस वर्ष भी बराबर होता आया है । सवाल यह नहीं है कि यार्न मिल नहीं रहा है, सवाल यह है कि यार्न मिलने के बावजूद भी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है । इसलिए मेन समस्या जो हम लोगों के सामने है वह यह है कि हमारा गरीब बुनकर जो है उसको हैंक यार्न कैसे मिले ताकि

उसको बुन करके वह अपनी जीविका कमा सके जो बुनकर कोआपरेटिव सैक्टर के माध्यम से जुड़े हुए हैं या आन्ध्र प्रदेश में जो उनके प्रोडक्शन सैन्टर हैं उनके माध्यम से जुड़े हुए हैं वह तो फिर भी उनको मजदूरी मिल जाती है क्योंकि उनको यार्न उपलब्ध हो जाता है, उसको बुन करके वीविंग करके दे देते हैं तो उनको मजदूरी कम से कम उपलब्ध रहती है ज्यादा होती है, कम होती है, यह अलग बात होती है, परन्तु जो इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे जनता क्लाथ के अलावा जो बनाने वाले नहीं हैं गैर जनता क्लॉथ में जो काम करने वाले बुनकर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, हैक यार्न इतना महंगा हो गया है कि वह उसको खरीद नहीं सकते और जब खरीद नहीं सकते तो बना कुछ नहीं सकते और रोजी-रोटी का प्रश्न उनके सामने रहता है। आंध्र प्रदेश के जिन तीन जिलों के नाम लिए गए हैं—प्रकाशम, गुंटूर और कृष्णा वह तो हैं ही उनके अलावा भी लोगों की हालत बहुत खराब है। इसलिए सवाल यह है कि उन लोगों को कैसे हम मदद कर सकें जिससे कि वह लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकें?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं जैसे मैंने अपने वक्तव्य में कुछ स्कीम्स की घोषणा की है, हम चाहेंगे कि वह एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन जिलों में शुरू हो और उनके रिजल्ट्स जो आए उनको देखते हुए हम जैसे उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, जहां-जहां भी इस प्रकार की समस्याएं हैं वहां भी हम कैसे इस स्कीम को लागू करवा सकें, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही आठवीं पचवर्षीय योजना जो बन रही है, उसमें हम हैंडलूम वीवर्स के लिए कैसे योजना बना सकें और उनको लाभ मिल सके, उस दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि यह मेरा मानना है और माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हो सकता है कई जगह सहकारिता क्षेत्र में करप्सन हो वह कुछ मिडिल मेन की तरह काम करते हों, लेकिन जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया, कई जगह कोआपरेटिव सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है, उस के माध्यम से वीवर जुड़ा हुआ है और उनको पूरा पैसा भी मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम आंध्र प्रदेश के अंदर जो योजनाएं मैंने वक्तव्य में बतायी हैं, उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अधिक-से-अधिक वीवर्स को-आपरेटिव सेक्टर में प्रवेश करें, उनके साथ वह जुड़ सकें। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो उत्पादन सेक्टर है, उनके साथ भी जुड़ने वाली बात है। हमारे सामने प्रश्न है कि कैसे उनको जोड़ा जाए, कैसे उनको प्रोत्साहन दिया जाए? वह सारी स्कीम्स बना रहे हैं।

जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, सरकार का यह मानना है कि आज जो हमारे ट्रेडीशनल वीवर्स हैं, उनकी माली हालत जैसीकि हम लोगों ने बयान की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जब तक हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब तक हम उनको ट्रेडीशनल आयटम्स से निकालकर जो हाई कास्ट आयटम्स हैं उनकी तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक उनकी माली हालत सुधरने वाली नहीं है। एक वीवर अगर दिनभर काम करता है, अगर उसको यार्न मिल भी जाता है, अगर कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से मिलता है तब भी देखने में आता है कि उसको दिनभर का जो वेज मिलता है, वह बहुत कम होता है। इसलिए हाई कास्ट आयटम्स में जो वीवर्स चले गए हैं, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में, वह अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि आठवीं पंचवर्षिय योजना में इस प्रकार की योजना बनायी जाए जिससे कि उनको हम अच्छी-से-अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, उनको हाई कास्ट आयटम्स की तरफ मोड़ा जा सके ताकि उनको अच्छा वेज मिल सके। हैंडलूम को जब तक माडर्नाइज नहीं करेंगे, वह ज्यादा माारीरिक

[श्री अशोक गहलोत]

श्रम करने के बावजूद कम पैसा कमाएगा उसके लिए भी हमारी कोशिश है कि हम लोग आर.एन.डी. वर्क के माध्यम से हैंडलूम में इस प्रकार की टैक्नालॉजी पैदा करें, उनको इस प्रकार इंप्रूव करें जिससे कि वह कम मेहनत कर के ज्यादा पैसा कमा सके।

यार्न सप्लाई को इंश्योर करने के लिए भी प्रागदा कोटैया जी ने यहां तक कह दिया कि उसके लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो बनाना चाहिए। इस बारे में इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हमारी मंशा यह रही है कि कैसे हम अधिक-से-अधिक पैदा करें जिससे कि हैंक यार्न बुनकरों को पूरा मिलता रहे, अच्छी क्वालिटी का मिले और एक निश्चित दाम पर मिल सके। मिलों के साथ क्या कर सकते हैं, जैसे आज हैंडलूम ऑब्लीगेशन स्कीम बनी हुई है हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम लोग विचार कर, कोई ऐसी योजना बने जिससे कि मार्केट के अंदर यार्न उपलब्ध हो सके और उसके दाम के आधार पर हो सके। हमने ग्रुप इंश्योरेंस की जो योजना लागू करने की बात सोची है जिसमें स्टेट और सेंट्रल मिलकर फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट कंट्रीब्यूशन कर के जिसमें कि वीवर्स को कोई प्रीमियम न देना पड़े, इस बारे में भी हम चाहेंगे कि जो योजना आंध्रप्रदेश के कुछ जिलों में शुरू हो रही है, वहां की स्थिति को देखते हुए धीरे-धीरे और भी जगहों पर यह लागू हो सके क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो हालात बने है, उनके कारण बैंकों ने अपने लोन देना कुछ कम कर दिया है। वह भी एक प्रोब्लम बहुत बड़ी प्रोब्लम है क्योंकि उसके माध्यम से आज जो सोसायटी है उनको पूरा लोन नहीं मिल पा रहा है और नबाड की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो यह मेटर फाइनेंस मिनिस्टरी के अन्दर पेंडिंग है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : फाइनेंस मिनिस्टर यहां हैं। यह आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : जी। इन की मिनिस्टरी में पेंडिंग है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी उस मसले को हर करवायें जिससे कि हैंडलूम में काम करने वाली जो सोसायटी हैं या दूसरी संस्थायें हैं, उनको प्राइरिटी पर बैंकिंग सुविधा और दूसरी सुविधायें मिल सकें। तो मैं समझता हूं कि वह भी उनको मदद करेगी गरीब बुनकरों तक यार्न को पहुंचाने में, जो कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में, जो हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट होता है उसकी पालिसी में हमने दो परसेंट का कोटा इसका रखा है, जिससे हैंडलूम का आईटम एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिये अभी हमने कोई एक महीना पहले ही व्यवस्था की है ताकि हैंडलूम में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और वीवर्स के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो डिटेल में बहुत कुछ कहने को है क्योंकि बहुत से पाइंटस उठाये गये हैं, लेकिन चूंकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आंध्र प्रदेश से संबंधित है इसलिये मैं दो-तीन पाइंट्स पर ही निवेदन करूंगा। आंध्र प्रदेश वस्त्र विकास निगम ने उन्पादन केन्द्र खोले हैं, यहां करीब चिराला में 1500 और कनागाला में 1100 बुनकरों को शामिल किया गया है। भट्टीपोरूलू और मछलीपट्टनम में विद्यमान उत्पादन केन्द्रों में 1200 अतिरिक्त बुनकरों को सहकारिता में शामिल करने का भी निश्चय वहां हुआ है। चिराला के निकट इप्पू रूपालम् में एक नई बुनकर समिति स्थापित करने का भी निर्णय कुछ लिया है। हम लोग वहां के मुख्य मंत्री के बराबर संपर्क में है। अभी पिछले सप्ताह ही दिल्ली के अन्दर उनके साथ कामर्स मिनिस्टर चिदम्बरम साहब की और इस मिनिस्टरी के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने, उनके सदस्यों की भावना, जो मझे बराबर

मिलती रहती है, उनसे उनको अवगत कराया । मैं समझता हूं कि वह स्थिति की गंभीरता को समझते हुये आने वाले वक्त में और ऐसे कदम उठायेंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके और बुनकरों की वहां पर जो समस्या है, उसको हल करने में कामयाब हो सकें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पालिसी के बारे में एक मुद्दा उठा था । कई माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया और माननीय राम नरेश यादव जी बोल रहे थे । उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आबिद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह जनवरी, 1990 में आ चुकी थी और करीब डेढ़ साल हो गया था पिछली सरकार को, उसके द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । परन्तु, इस का गठन सरकार होते ही हमने पहली बार यह कहा था कि हमने इस रिपोर्ट को टेकअप कर लिया है और चाहेंगे कि तीन महीने में इस रिपोर्ट को एक रिवाइज पालिसी के रूप में आपके सामने रखें । तीन महीने में हम लोगों ने सारी स्टेट गवर्नमेंटस से, वहां के आफीसर लेवल पर और पूरे सभी राज्यों के जो टेक्सटाईल मिनिस्टर हैं उनकी कांफ्रेंस भी कर ली । जो केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग हैं, मिनिस्टरी हैं उन के अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बात कर ली और हमारी मिनिस्टरी की तरफ से वह रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करके केबिनेट में भेजने की तैयारी कर ली है । मैं समझता हूं कि जो फार्मलटीज या कुछ नई इन्क्वायरीज मांगी गई हैं, वह हमारी मिनिस्टरी सबसे कोडिनेट करके भेज रही है । मुझे आशा है कि हम आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही उस रिवाइज स्पेशल पालिसी को रख सकें, जिससे कि जो बात कही गई थी माननीय सदयों को, वह पूरी कर सकें ।

महोदय, एक तरफ तो कोटन-ग्रोवर है, उनके इंटरेस्ट वाच करने का सरकार पूरा ध्यान रखती है और प्रतिबद्ध है कि जो कपास उत्पादन करने वाले किसान हैं । उनको पूरा लाभ मिल सके । दूसरी तरफ जो हैंडलूम वीवर्स हैं, उनके लिये भी सरकार पूरी तरह चिंतित है और उनके प्रति भी प्रतिबद्ध है कि कैसे उनको पूरा रोजगार मिले, कैसे उनके कल्याण के लिये कार्य कर सकती है । तीसरी तरफ, पावरलूम सेक्टर जो नया सेक्टर बन गया है यहां मैं समझता हूं कि कई गरीब बुनकर जो थे वह धीरे धीरे, जैसे कर्नाटक के अन्दर और कई प्रदेशों के अन्दर वहां की गवर्नमेंट ने ही हैंडलूम वीवरस को प्रोत्साहन दिया पावरलूम में जाने के लिये और वे लोग वहां चले गये । इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है । नई टेक्सटाइल पालिसी जो रिवाइज टेक्सटाइल पालिसी के रूप में होगी, आबिद हुसैन साहब की रिकमंडेशन के आधार पर होगी और इस प्रकार से देश के सामने आयेगी, जिससे तीनों सेक्टर अपने अपने तरीके से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें । जहां तक 22 आइटम्स का सवाल है, जिनको रिजर्वेशन एक्ट के माध्यम से माननीय प्रागदा कोटेया और कई अन्य सदस्यों ने भी उस बात को उठाया था, मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि पिछले सैशन में मैंने खुद ही वह कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि अगले सैशन में हम 9वें शैडयूल में लाने वाली बात संविधान में संशोधन करके हम लोग लायें । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्वाइंट को लेकर प्रधान मंत्री स्तर पर और दूसरे माननीय सदस्यों, जो केबिनेट के हैं, उनके स्तर पर भी हमने चर्चा की है और लॉ मिनिस्ट्री के सुझाव पर कि अगर हम 9वां शैडयूल रखेंगे तब भी जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गये हुये हैं, क्योंकि पूरे देश के अन्दर करीब 32 पेटीशन लग गई थी, स्टे मिल गया था । हम लोगों

[श्री अशोक गहलोत]

ने कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट में सारे केसिज मंगा लिये हैं और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो लॉ मिनिस्ट्री का एक प्वाइंट था कि अगर हम 9वें शैडयूल में इसको लेकर चेंज करेंगे संविधान में, तब भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ हम चाहते हैं, वह न मिल सके । इस बात को सोचते हुये हमने कोशिश की कि सेंट्रल लॉ एजेंसी के माध्यम से हम यह कोशिश करें कि जल्दी ही ये केस अंतिम सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट में आ जायें जिससे कि समस्या का समाधान हो जाये और 22 आइटम्स के बारे में जो बात है, वह हम पूरी कर सकें और एक्ट को लागू कर सकें । आपको जानकर खुशी होगी उपसभाध्यक्ष महोदय, कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में यह उल्लेख हुआ था और उसके बात यह तय हुआ है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिये केस लग रहा है । यह माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने अपना आदेश दे दिया है, दूसरे न्यायाधीशों से पूछकर के, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी के अन्दर यह मामला हल हो जायेगा और उसके माध्यम से जो समस्यायें उठाई गई हैं, उनका अपने आप समाधान हो जायेगा ।

स इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय दस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मन से अपनी पीड़ा को, जो उनकी भावना थी और जो बुनकरों के प्रति समर्पित है, उसको उन्होंने अपने शब्दों में यहां व्यक्त किया । मैं उनका यकीन दिलाना चाहूंगा कि जिन प्वाइंटस का मैं यहां जवाब नहीं दे पाया हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि उन पर मिनस्ट्री में बराबर विचार होता रहे और हम लोग बुनकरों की और इस सेक्टर की समस्याओं का समाधान करते रहें । धन्यवाद ।

SHRI CHHOTUBHAI PATEL (GUJARAT) : Sir, onlyone minute... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The subject is closed now.... (*interruptions*)....

श्री छोटूभाई पटेल : सरकार की नई अर्थ नीति के संदर्भ में..... (व्यवधान)....

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, in regard to ex-gratia payment with which all of us are concerned and have expressed our disatsfaction, I would like the Minister to respond. Secondly, the loan with its interest is to big a burden and hence interest-free loans must be advanced liberally to the hand loom weavers.... (*interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Yes, Mr. Ghelot, do you want to respond? .... (*interruptions*)....

श्री अशोक गहलोत : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक्सग्रेशिया पेमेंट की जहां तक बात है, जैसा मैंने निवेदन किया, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से यह बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई है कि भूख से कोई मौत नहीं हुई बल्कि मौत हुई है बीमारी से या वृद्धावस्था से या अन्य किसी कारण से । इसलिये उनका यह कहना है कि कोई मौत ऐसी नहीं है जिसके आधार पर हम एक्सग्रेशिया पेमेंट दे सकें । हम लोगों ने उनसे यह बात कही कि जो मानवीय भावना है, उसके आधार पर आप कुछ करें । मुख्यमंत्री जी ने 5000 रुपये की बात इसलिये कही है ताकि अपने लोगों की मदद कर सकें । जहां तक (व्यवधान)..

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : Even if starvation deaths are taking place, the State Government would have issued.. (*interruptions*).... to the Centre to cover it up....(*interruptions*)...

श्री अशोक गहलोत : जिला अधिकारियों के माध्यम से जो रिपोर्ट आयेगी, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि चाहे किसी पार्टी की सरकार कहीं पर भी हो, जो रिपोर्ट

रिपोर्ट वह जिला अधिकारियों के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के पास आत है। ...(व्यवधान)...

SHRI MENTAY PADMANABHAM : We have been requesting the Minister to visit these places and evaluate the position..(*interruptions*)...

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: The situation is very grave....(*interruptions*)....We have been requesting the Minister for the..(*interruptions*).... for thep ast one and a half month..(*interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, the people were given twenty five thousand rupees, the families of those who died during the cyclone by the Central Government...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The Minister has heard you and he will reply....(*Interruptions*)....

SHRI V. NARAYANASAMY : Here also, Sir, they should be duly compensated..(*Interruptions*)...

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, we are inviting the Minister to visit those places. The Minister should respond to that. It is an invitation extended by all the parties here... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJ I MASODKAR) : He does not need an invitation..(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की रिपोर्ट अगर सही है तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो जुलाहे मारे गये हैं, इनके इलाके में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर यह रिपोर्ट दी है कि यह मौत भूखमरी के कारण नहीं हुई हैं तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मासिक आय क्या थी और कितना बिजनेस सरकार ने उनको दिया था ?...(व्यवधान) यह भी बतायें तभी हमें पता लगता है...(व्यवधान) कितनी खरीद फरोख्त की गयी है उनके माध्यम से, यह पहले बताने की कृपा करे?

SHRI V. NARAYANASAMY Sir, in the "Frontline" it has been written that the correspondent visited those areas and was satisfied... (*Interruptions*)... that the handloom weavers died due to starvation only.. (*Interruptions*).. It is written here in this magazine, "Front line".. (*Interruptions*).. So, the Minster should come to the rescue of these people who have been affected.. (*Interuptions*)

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO : Sir, ther have been hunger deaths,.. (*Interruptions*)... starvation deaths. He should not take it lightly.. (*Interruptions*)...

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY : Sir, he is not coming out even with an assurance that he will visit those areas. What is this? .. (*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Reddy, please sit down.. (*Interruptions*)...

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, there should be a Committee of the House to go into the question.. (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The Minister has heard you. Please sit down.... (*Interruptions*)..... Yes, Mr. Yadav, what do you want to say?

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि यह जो मौतें हुई हैं, इस पर मंत्री जी को और सरकार को कोई कष्ट मालूम नहीं पड़ता है। यह भूखमरी से मौतें हुई हैं, सबकी यही राय है और यह सही बात भी है। लेकिन इस तथ्य को बिल्कुल लाईटली लिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : No, no, That is not correct. He is not taking it lightly... (*Interruptions*)..

श्री ईश दत्त यादव : मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं कि इस तरह की मौतों की आशंका और पुनरावृत्ति

[श्री ईश दत्त यादव]

उत्तर प्रदेश के अन्दर होने वाली है। आप नोट करलें कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हैण्डलूम और पावरलूम का सबसे ज्यादा कारोबार है--मऊ, मुबारकपुर, मगहर, बस्ती जिले में और बनारस व बाराबंकी के अन्दर। मान्यवर, जो बनारसी साड़ियां दुनिया के अन्दर बनारसी साड़ी के नाम से बिकती हैं वह मेरे जिले मऊ और मुबारकपुर में बनती हैं, उनकी फिनिशिंग बनारस में होती है। सूत न मिलने की वजह से मऊ और मुबारकपुर, मगहर के जो तमाम बुनकर हैं वह... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNA JI MASODKAR) : No, no. Please take your seat. Let us not open that subject again..(*Interruptions*)....

श्री ईश दत्त यादव : मैं ओपिन नहीं कर रहा हूं। मैं नया सब्जेक्ट मंत्री जी को दे रहा हूं। वह जांच करा लें और तुरन्त सूत की सप्लाई करायें, क्योंकि अगर इन जगहों पर सूत नहीं मिलने पर इन बुनकरों की हालत खराब होती जा रही है, जिस ओर तत्काल ध्यान दिया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Please sit down. As you are aware, I have already formulated my own observations and the Minister is aware of it. Yes, Mr. Patel.

श्री छोटूभाई पटेल : महोदय, सरकार की नयी अर्थ-नीति और नयी औद्योगिक नीति के संदर्भ में क्या सरकार रिलीवेंट मिनिस्ट्री--एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड नेस के साथ मिलकर, जिससे दोबारा मरी न आये, जीवन समाप्त करने का मौका दोबारा न मिले तो कोई कम्प्रेहन्सिव पौलिसी बनाने पर विचार कर रही है?

डा० रत्नाकर पांडेय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर बनारस में करोड़ों बुनकर रहते हैं और ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Pandey, you have not begun, but you stop now !..(*Interruptions*)....

SHRI SUKOMAL SEN (WEST BENGAL) : Sir, give a chance to this side also..(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Then we will really be opening the debate and that is not permissible.... (*Interruptions*)....

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, we would only like to extract some concessions for the poor weavers. That is all.... (*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : I can understand that. Please sit down.. (*Interruptions*)....

डा० रत्नाकर पांडेय : उत्तर प्रदेश में करोड़ों बुनकर बनारसी साड़ियां बनाकर कई सौ करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज भारत सरकार को देते हैं लेकिन बीच में जो कोठी वाले साड़ी खरीदते हैं और जो बड़े-बड़े कोआपरेटिव आपने नेशनल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए हैं, उसमें बहुत सी जाली कोआपरेटिव्ज हैं। सारा रेशम यहां से जाता है, उसको कुछ पूंजीपति लोग कोआपरेटिव बनाकर बेच देते हैं और हमारे जो बुनकर हैं उनके घरों में औरतें टी.बी. से पीड़ित हैं, बच्चों की फीस देनी है, जाड़े में पहनने को कपड़ा नहीं है... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप सवाल पूछिए।

डा० रत्नाकर पांडेय : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। बुनकर को केंद्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो रेशम या बुनने का रॉ-मैटीरियल दिया जाता है, चाहे वह जरी हो, चाहे सिल्क हो, वह सही ढंग से उस तक नहीं पहुंच पाता है। जब वे साड़ियां बनाते हैं तो वे भी उनसे डायरेक्ट परचेज नहीं की जाती हैं बल्कि मिडिलमैन के माध्यम से परचेज की जाती हैं और उसमें बहुत जालसाजी होती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : उन्होंने जवाब दे दिया है।

He has said that he would look into it.

डा० रत्नाकर पांडेय : बीच में सत्ता के दलाल कोआपरेटिव बनाकर बुनकरों का शोषण करते हैं। महोदय, बनारस में भी कई दर्जन लोग हर साल अभाव में, पीड़ा में और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने के कारण मर जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? जो मिडिलमैन उनका शोषण करते हैं, उनको सजा देने के लिए आपकी सरकार ने क्या उपाय किए हैं क्योंकि यह सरकार तो "पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट" में विश्वास रखती है। तो आपके पास क्या उपाय है इसको रोकने के लिए, यह सदन जानना चाहता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : जाधव जी, आपका क्या प्रश्न है?

श्री **विटठलराव माधवराव जाधव** : मंत्री जी, आपको शायद मालूम होगा कि महाराष्ट्र में "पैठनी" नाम की साड़ियां बनती हैं और उनका एक्सपोर्ट होता है। ये साड़ियां पांच-पांच, दस-दस हजार में बेची जाती हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र के इन बुनकरों के लिए सरकार कोई ऐसी योजना बनाएगी कि जिससे बुनकरों को भी सुविधा हो और सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल सके और इन साड़ियों के एक्सपोर्ट में भी सुविधा हो। सरकार इस बारे में क्या कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमान (आंध्र प्रदेश) : महोदय, दौराने डिबेट एक मुअज्जिज मेंबर ने यह सुझाव दिया था कि क्या बुनकरों को उनके पेशे में मदद के लिए इंट्रस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, इस बारे में मिनिस्टर साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि स्टार्वेशन डैथ्स को मिनिस्टर साहब ने कबूल नहीं किया है। मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि इस बारे में एक हाऊस कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे कि वाकई ये डैथ्स स्टार्वेशन के कारण हुई हैं या किसी और कारण से हुई हैं।

†[شری خلیل الرحمان : مہودے-

دوران ڈبیٹ ایک معزز ممبر نے یہ
یہ سجھاؤ دیا تھا کہ کیا بنکروں کو
انکے پیشے میں مدد کیلئے انٹریسٹ
فری لون دیا جائیگا - اس بارے
میں منسٹر صاحب نے کوئی رپلائی
نہیں دیا ہے - میرا دوسرا پوائنٹ
یہ ہے کہ اسٹارویشن ڈیتھس کو
منسٹر صاحب نے قبول نہیں کیا
ہے - میں سدن سے درخواست
کروں گا کہ اس بارے میں ایک
ہاؤس کمیٹی بنائی جائے جو اسکی
جانچ کرے کہ واقعی یہ ڈیتھس
سٹارویشن کے کارن ہوئی ہیں یا
کسی اور کارن سے ہوئی ہیں -]

SHRI SUKOMAL SEN : Sir, I am on a very limited point. I have a suggestion to make about the starvation deaths. Now the Government denies it, both the Andhra Pradesh Government and the Central Government. My only suggestion is that at least the Government can sponsor an all-party delegation to visit that place and determine whether the deaths were due to starvation or some other reasons. And then they can report back to the Parliament. (*Interruptions*)

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Sir, Sambalpuri sarees are very famous in India and they also earn a lot of foreign exchange for our country. But in our Orissa, the condition of our weavers is very pitiable.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : He will look into it.

SHRIMATI MIRA DAS : Specifically I want that the Sambalpuri weavers who bring out those very famous sarees should be given additonal help from the Government. And the Government should specifically evolve a policy to help these handloom weavers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Would you like to respond, Mr. Minister? (*Interruptions*)

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu) : Every Member is given a chance to speak, why not met I want to know whether the Government is paying dues to the cooperative weavers. society. A lot of amount is overdue. The Government has to pay this amount; it has not paid it as yet. (*Interruptions*).

SHRI PRAGADA KOTAIAH : As far as the starvation deaths are concerned, has has deputed the Additional Development Commissioner on the 6th of September to Prakasam, Guntur and Krishna districts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Kotaiah, please sit down. Nothing is going on record.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : *

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL (Uttar Pradesh): Sir, is it going on recrod ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : This is not going on record.

6.00 P.M.

SHRI PRAGADA KOTIAH : The Minister need not depend upon the version of the Chief Minister.. (*Interruptions*).

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Kotaiah, it is not going on record. Please sit down.

SHRI PRAGADA KOTIAH : *

*Not recorded.

श्री राम नरेश यादव : स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य मंत्री रिएक्ट करें । (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बुनकरों की हालत वास्तव में खराब है । सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं और भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर वास्तव में बुनकरों की हालत ठीक नहीं है । ठीक क्यों नहीं है इस बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं और ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई करनी है इस बारे में भी कह चुका हूं । उन बातों में नहीं जाना चाहता केवल दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं ।

श्री राम नरेश यादव : सभी सदस्यों की राय है कि आप खुद जाइये । आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : टैक्सटाइल बंद हो जाते हैं, मजदूर बेकार हो जाते हैं । (व्यवधान) समय रहते इसको देखा जाए । गरीब बुनकरों का घर जाकर देखिये, उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं । (व्यवधान) आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वहां जाकर वह देखकर आयें ... (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM : I have a small submission to make. There is a lot of controversy over the starvation deaths. The State Government had taken a different view where as the Textile Commissioner who is working under the Textile Ministry has taken another view. And we know that starvation deaths have taken place. Therefore, in the circumstances, we demand that a delegation from this House should go to that place and examine and interact with various sections of the people and make a report. I want to know whether this sugestion is acceptable to the Government or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : You are a leader of the opposition ; you know the procedure.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : I am only appealing to the Minister. Will the Minister agree?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Let us go in an orderly way.

श्री राम नरेश यादव : बात हो रही थी मंत्री जी वहां जायें और इन्होंने दूसरे सवाल को उठा दिया। **(व्यवधान)**

श्री अशोक गहलोत : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, सारे माननीय सदस्यों की एक ही भावना है कि बुनकरों की माली हालत सुधरे। मैं आपको शुरू में कह चुका हूं.... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : हम सब यह चाहते हैं कि सरकार झूठ न बोले और अगर झूठ बोले तो उसको... **(व्यवधान)**

†[شری محمد افضل عرف م- افضل :
ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جھوٹ نہ بولے ار اگر جھوٹ بولے تو اسکو .... (مداخلت) ...]

डा० रत्नाकर पांडेय : सरकार झूठ बोलती नहीं है। सरकार जो बोलती है वह करती भी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us put an end to it.

श्री अशोक गहलोत : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि इस इसू को ले करके प्रधान मंत्री जी के स्तर पर बात हो चुकी है और यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी, मैं समझता हूं कि इस बात को सभी जानते हैं कि उन सभी का कमिटमेंट जिन्दगी भर हैण्डलम वीवर्स के [illegible] रहा है। आज की स्थिति के बारे [illegible] चर्चा हो चुकी है। प्रधान मंत्री जी पहले से ही कह चके हैं कि कामर्स मिनिस्टर और म, दोनों इन जिलों में जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं। सवाल यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वह मैं आपको बताना चाह रहा था.... (व्यवधान)।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : आप जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद कम से कम हमको कोई रिपोर्ट देंगे या नहीं ?

श्री अशोक गहलोत : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले मैं एक दो पाइन्ट्स निवेदन कर दूं। एक तो सम्बलपुर और पैंठनी के बारे में जो बात आपने कही है उसके बारे में अगर आप अलग से लिख-कर दे देंगे तो उसकी इत्तिला मैं आपको दूंगा और अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी करूंगा। श्री रत्नाकर पाण्डेय जी ने बनारस के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे अलग से लिखकर मेरे पास भेज दें तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फैसला करेंगे.... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जांच तो कई बार हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आया है। जो लोग जांच करने जाते हैं वही सारे भ्रष्टाचार से जुड़े होते हैं.... **(व्यवधान)**

श्री अशोक गहलोत : श्री अहलुवालिया जी ने एक बात कही कि उस वक्त खरीदारी हुई है या नहीं हुई है। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि अप्रैल 1990–91 और अगस्त 1990-91 के बीच में राज्य का जो एपेक्स हथकरघा अधिकरण है उसने करीब 98.96 लाख रुपये का यानी एक करोड़ का कपड़ा इस बार खरीदा था.... (व्यवधान)। गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 42.26 लाख रुपये का कपड़ा खरीदा गया था। पिछली बार 42 लाख का और इस बार एक करोड़ रुपयों का कपड़ा उपलब्ध हुआ है, खरीदा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि खरीदारी में कोई देरी हुई हो।

एक पाइंट ड्यूज के बारे में भी उठाया गया है। ड्यूज देने में कोई देरी हो रही हो तो उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त करूंगा कि देरी क्यों

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री अशोक गहलोत

हुई, क्या कोई डिफाल्टर सोसायटी तो नहीं है या कोई और कारण है तो उसके बारे में जानकारी करके माननीय सदस्यों को बताऊंगा ।

अंत में आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से और सदन से अपील करना चाहूंगा कि पिछली बार यह चर्चा हुई थी तब मैंने कहा था कि जल्दी ही एक टीम भेजूंगा । उस वक्त वहां पर दो-तीन मौतों की खबरें आई थीं । इस मामले को सीरियसली लेकर और सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और आप लोग इस बारे में बोले भी थे, तो हमने टीम को भेजा । मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यह मानवता से संबंधित मुद्दा है, टीम भेजने के बाद हालत यह हुई कि इस इसू को राजनैतिक रूप देने की कोशिश की गई और आन्दोलन भी हुआ । और जो खबरें आई उससे यह पता चलता है कि इस मामले को एक राजनतिक इसू बनाया जा रहा है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आपकी भावनाओं को देखते हुए स्वयं देखकर आऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसको कम से कम राजनैतिक इसू न बनाया जाए, यह बात आप अपनी-अपनी पार्टी के सदस्यों को कहें ।

SHRI MENTAY PADMANABHAM : I seek your protection. I don't understand what the Minister is saying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at nine minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 5th December, 1991.